RNI NO. DELHIN/2008/23723

आईए जानते हैं इन दिनों सीएम योगी की ...

₹ 10/-

संपूर्ण माया

समाचार पत्रिका

वर्ष 13 ,अंक 4 ,मई 2020

www.sampurnamaya.in

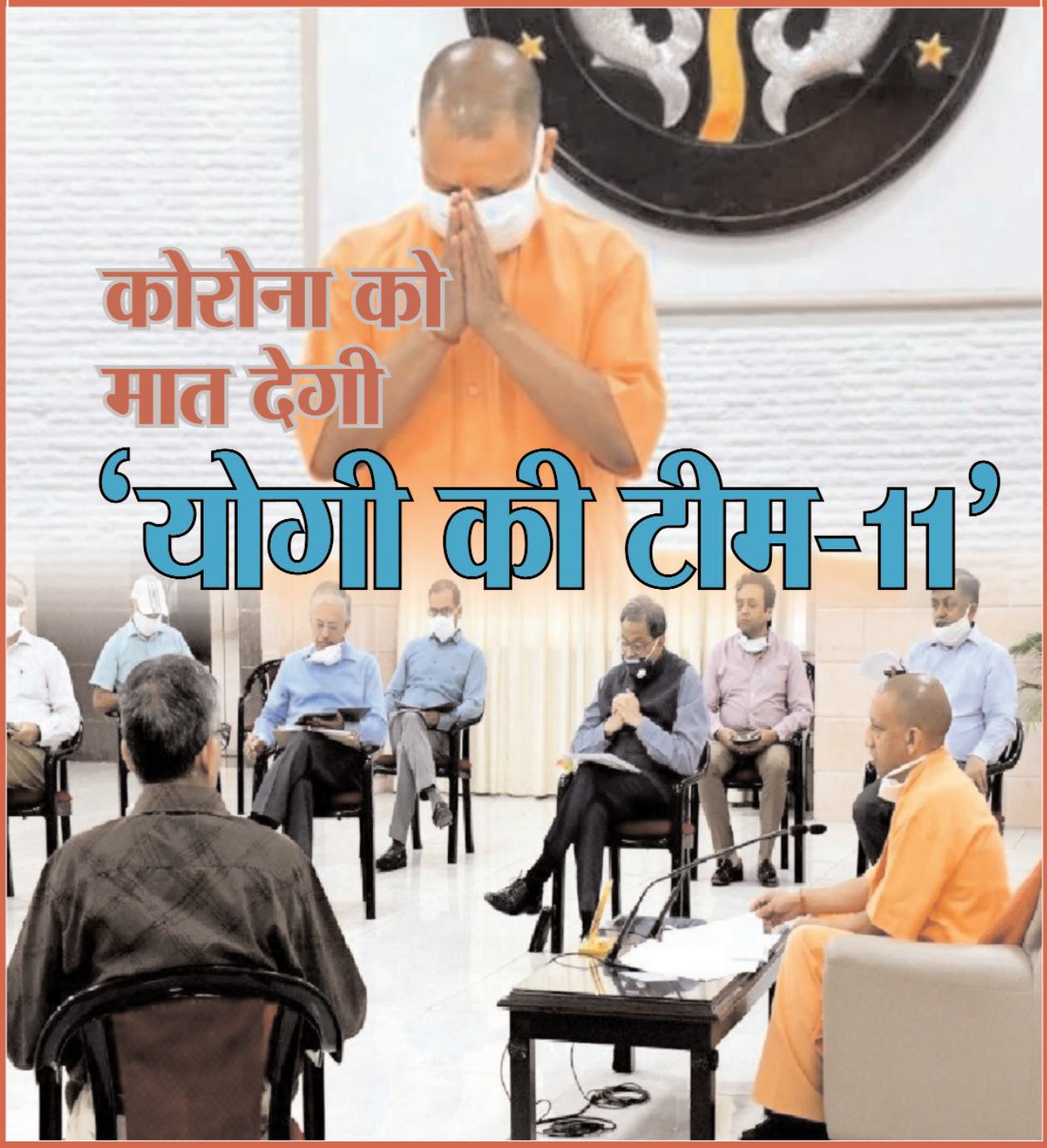

कोरोना को मात देगी

‘योगी की टीम-11’

दिनभर की और मासिक
खबरों के लिये
संपूर्ण माया
लॉगिन करें ...
http://www.sampurnamaya.in
संपूर्ण माया
समाचार पत्रिका
सम्पूर्ण माया पत्रकार समूह से जुड़ने के लिये सम्पर्क करें
sampoornamaya@gmail.com
7905230036
@Rummyculture
Register & get ₹310 Assured Bonus
+ ₹5250 Welcome Bonus
REGISTER NOW

संपूर्ण माया
समाचार पत्रिका

वर्ष 13, अंक 3, अप्रैल 2020

स्व. क्षितींद्र मोहन मित्र
स्व.आलोक मित्र
स्व. दीपक मित्र
प्रेरणास्रोत

स्नेह मधुर
संपादक

रवींद्र श्रीवास्तव
वरिष्ठ सलाहकार संपादक

आलोक एम. इन्दौरिया
सलाहकार संपादक

खड़क बहादुर सिंह
राजनीतिक सलाहकार

शशि किरण
कानूनी विशेषज्ञ

ब्यूरो

प्रदेश : देवदत्त दुबे
बिहार : जीवेश कुमार सिंह
उत्तराखंड : राम प्रताप मिश्रा

संवाददाता

(नागपुर) अपर्णा महादानी
(प्रतापगढ़) सौरभ सिंह सोमवंशी

कार्यालय

दिल्ली: जी एच 1/32, अर्चना आपार्टमेंट पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63
लखनऊ: के-4,वनास्थली अपार्टमेंट गोमती नगर एक्सटेन्सन लखनऊ -010
भोपालरू फ्लैट-बी-103 कन्हैया अपार्टमेंट शहापुरा, भोपाल
इलाहाबाद : 1/ए हाशिमपुर रोड, टैगोर टाऊन, प्रयागराज-211002

प्रकाशन एवं मुद्रक, श्री संदीप मित्र द्वारा जी.एच 1/32,अर्चना अपार्टमेंट पश्चिम विहार,नई दिल्ली-63 से प्रकाशित एवं करन प्रिंटर्स एफ-29/2, ओखला फेस-3 नई दिल्ली से मुद्रित

प्रकाशक की आज्ञा के बिना कोई रचना उद्घृत नहीं की जानी चाहिए।

अन्दर

कोरोना के खिलाफ जंग में हर व्यक्ति तक पहुँची 'योद्धा योगी' की टीम ... 05

मौत के सौदागर तब्लीग़ियों पर किस-किसकी ...11

कोरोना महा संकट : अंध विश्वास का नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें ... -16

आइये जानते हैं इन दिनों में मुक्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिनचर्या के बारे में ?

✍ संदीप मित्र

इन दिनों नवरात्र संपन्न हो रहा है, मुख्यमंत्री जी हमेशा के तरह इस बार भी नौ दिन का व्रत रखे हैं। मुख्यमंत्री जी का दिनचर्या भोर में 4 बजे आरम्भ हो जाता है। उठते ही, स्नान, ध्यान और योग को नियमित करते है।इसके पश्चात देश, दुनिया के खबरों के लिए प्रातः 6:30 बजे से अख़बारों से प्रतिपुष्टि प्राप्थ करते है और लोगों से फ़ोन पर बात करके पूरे प्रदेश का हाल चाल लेते हुए 9:30 तक सरकारी काम शुरू कर देते है । उनके कुछ करीबियों से पता चला है की, पिछली कई रातों से वे ठीक से सोए नहीं है ,कारण बाहर से आ रहे लोगों को सकुशल पहुँचाने की चिंता है उनको। बीते दिन के उनके वस्थता के बारे में आइये जानते है ।

सुबह 9:30 बजे, बैंक अधिकारियों व पंचायती राज के अधिकारियों से मुलाक़ात कर मनरेगा श्रमिकों के भुगतान की पूरी प्रक्रिया समझे । फिर 10 बजे - मनरेगा श्रमिकों के हित में एक बटन दबाकर छह सौ 11 करोड़ रुपये के सीधे भुगतान के बाद लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये बात की।11:30 - यह कार्यक्रम ख़त्म होते ही, करोना को लेकर रोज़ाना की तरह ही टीम इलेवन के अधिकारियों के साथ बैठक की, ज़रूरी हिदायत दी और नोएडा के दौरे पर निकल गए। नोएडा पहुँचे, एरियल सर्वे किया, बैठकें की, देर रात तक अधिकारियों के साथ समीक्षा करते रहे। अगले दिन सुबह जल्दी उठे और ग़ाज़ियाबाद निकल गये, वहाँ अस्पतालों का मुआयना किया। अचानक तबलीगी जमात का विषय आ गया, जो की आज पुरे देश में कोरोना वृद्धि का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तत्काल मुख्य मंत्री जी विमान से लखनऊ आ गए । दोपहर 12:15 बजे आवास पहुँचे और 12:30 टीम ग्यारह के अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी। 2 बजे बैठक ख़त्म होने के बाद ज़रूरी काग़ज़ों पर दस्तख़त किए और प्रदेश भर का प्रतिपुष्टि लेने के बाद शाम को फ़ोन द्वारा और लोगो से जानकारी जुटाने लगे। ■

कोरोना को मात देगी 'योगी की टीम-11'

✍ लखनऊ ब्यूरो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम-11 कोरोना को मात देगी। ये टीम कोराना से उत्पन्न हालात पर तय जिम्मेदारी के अनुसार नजर रखेगी। सरकार ने कई विभागों को जोड़कर 11 कमेटियां बनाई हैं।

जिसमें सरकार के करीब दो दर्जन वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इनकी निगरानी एक कोच की तरह मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं।

1 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समन्वय कमेटी में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन सदस्य होंगे। इनका कार्य भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना, शिक्षा ने जुड़े सभी विभागों और सेवायोजन विभाग के माध्यम से सभी छात्रों व काम करने वाले लोगों को, जहां है, वहीं पर रहने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरुक करना।

2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, श्रम एवं सेवायोजन सदस्य होंगे। इनका कार्य श्रमिकों और अन्य गरीबों को समय से भरण पोषण भत्ते का वितरण सुनिश्चित कराना होगा। प्रदेश की औद्योगिक व व्यावसायिक ईकाइयों में काम करने वाले कार्मिकों (नियमित, दैनिक वेतन, संविदा पर) को बंदी के दौरान पूर्ण वेतन, मानदेय सुनिश्चित कराना। इसके साथ ही इनसे संबंधित समस्याओं का शासन एवं जिला प्रशासन स्तर पर आवश्यक निराकरण सुनिश्चित कराना होगा।

3. कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी में प्रमुख सचिव, कृषि, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, दुग्ध विकास एवं पशुधन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, अपर पुलिस महानिदेशक(कानून व्यवस्था), निदेशक, मंडी एवं राहत आयुक्त सदस्य होंगे। इनका कार्य आवश्यक सामग्री एवं वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए जनपदों से समन्वय स्थापित करना होगा । अंतर्जनपदीय व जनपदीय परिवहन में आ रही समस्याओं का निराकरण कराना होगा। समिति पूरे प्रदेश में जनमानस को होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं यथा दूध, सब्जी एवं राशन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी आवश्यक सामग्रियां जनमानस को उचित मूल्य पर ही मिलें और बढ़ा-चढ़ाकर मूल्य लिए जाने की सूचनाएं प्राप्त न हों।

कई विभागों को जोड़कर मुख्यमंत्री योगी ने बनाई 11 कमेटियाँ

स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही लोगों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी कमेटी

4. अपर मुख्य सचिव, गह, सूचना एवं जनसंपर्क की अध्यक्षता में बनी कमेटी में पुलिस महानिदेशक(अभिसूचना) सदस्य होंगे। इनका कार्य लॉकडाउन में एन्फोर्समेंट की कार्यवाही की समीक्षा और मीडिया में तत्काल सही जानकारी उपलब्ध कराना होगा। जमाखोरों एवं कालाबाजारी में लिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना होगा।

5. अपर मुख्य सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में बनी कमेटी में राहत आयुक्त और इस कार्यालय ज्ञाप द्वारा गठित सभी समितियों के एक-एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे। इनका कार्य प्रदेश स्तर पर एवं सभी जनपदों में् कंट्रोल रूम की स्थापना व नियमित रूप से उनके कार्य की समीक्षा और यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति की जिज्ञासा व अनुरोध सही अधिकारी व विभाग तक अवश्य पहुंच जाए।

6. प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बनी कमेटी में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग सदस्य होंगे। इनका कार्य प्रदेश के सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं उसकी नियमित रूप से समीक्षा करना। इसके साथ ही पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा।

7. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सदस्य के तौर पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा/सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्योग रहेंगे। इस कमेटी का कार्य भारत सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस के सम्भावित एवं संक्रमित व्यक्तियों का प्रभावी इलाज एवं एवं देखभाल करना है। यहीं यह कमेटी प्रदेश में कोविड 19 से सम्बंधित चिकित्सीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने जिनमें चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड, दवाइयों एवं मास्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। होम क्वारेन्टाइन के अतिरिक्त अस्पतालों में क्वारेन्टाइन की सुविधा विकसित करने के साथ ही जनपद में मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना भी इस कमेटी का कार्य है।

8. प्रमुख, पशुपालन की अध्यक्षता में बनी कमेटी का कार्य पशुओं के चारे की व्यवस्था तथा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराना।

9. पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में बनी कमेटी प्रदेश के सभी जेलों, ट्रेनिंग सेंटर और पीएसी बटालियन में साफ-सफाई सुनिश्चित कराना है। साथ ही यह कमेटी का कार्य पीएसी बटालियन एवं ट्रेनिंग सेंटर में तैनात फोर्स को रिजर्व के रूप में तैयार करना है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फील्ड में तैनात किया जा सके।

10. अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी का कार्य कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन तथा भविष्य की रणनीति तैयार करना है। इस कमेटी में सदस्य के तौर पर प्रमुख सचिव, कृषि/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं गन्ना विकास एवं उद्योग रहेंगे।

11. प्रमुख सचिव, कृषि की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सदस्य के तौर पर में प्रमुख सचिव, उद्यान, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद शामिल रहेंगे। यह कमेटी किसानों की फसल जैसे गेंहू, आलू, सरसों इत्यादि के प्रभावी प्रक्योरमेन्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। ■

कोरोना के खिलाफ जंग में हर व्यक्ति तक पहुँची 'योद्धा योगी' की टीम 11

✍ लखनऊ ब्यूरो

पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। इस दरम्यान देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक योद्धा की तरह दिनरात 24 घंटे इस जंग के खिलाफ डट गए। उन्होंने प्रदेश के चुनिंदा 11 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाकर हर व्यक्ति तक सरकार की पहुंच को यकीनी बनाया। जनता ने इसे टीम-11 नाम दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गठित टीम-11 ने मुख्यमंत्री के ही सिद्धांत और रणनीति पर अमल करते हुए हर एक सदस्य ने अपने स्तर पर टीम-11 तैयार किया। ये टीम प्रदेश के शीर्ष यानि पंचम तल से लेकर जिले के कस्बे तक में तैयार हो गई। जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति तक पहुंचा, जो इस संकट की घड़ी में यह सोच कर परेशान था, कि उसकी मदद कौन करेगा।

एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम-11 के साथ प्रतिदिन अपने आवास पर समीक्षा बैठक कर कोरोना से निपटने के लिए अधिकारियों को आदेश-निर्देश दे रहे थे, वहीं योगी स्वयं ग्राउंड पर भी उतर आए। उन्होंने प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित जिले नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) पहुंच कर अधिकारियों को बेहतर कार्य करने का हौसला बढ़ाता तो लापरवाही बरतने वाले जिलाधिकारी को हटाने का कार्य़ भी किया। दिल्ली में यूपी सदन में बने कंट्रोल रूम का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री योगी यहीं रुकने वाले नहीं थे, वे लखनऊ में एसजीपीजीआई का दौरा कर कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाए गए अस्पताल और आईसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया। कम्युनिटी किचन जाकर स्वयं मुआयना किया कि भोजन की पर्याप्त व्यवस्था हो रही है की नहीं। एक तरफ जहां सभी लोग अपने घरों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रह थे, वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर पैदल ही घर वापस आ रहे मजदूरों से बातचीत करने मोहान स्थित टोल प्लाजा पहुंच गए। वहां से वापस आते रास्ते में अपनी गाड़ी रुकवा कर उन्होंने आलम नगर चौराहे पर लोगों से बातचीत भी की।

दिल्ली से जब उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को भगा कर उत्तर प्रदेश की सीमा में धकेल दिया गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्रवित हो उठे। उन्होंने रात भर जाकर करीब 3 लाख मजदूरों को बसों द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाया। जिस वक्त यह सब कार्य मुख्यमंत्री कर रहे थे, उस वक्त नवरात्रि का पवित्र दिन चल रहा था, मुख्यमंत्री व्रत रखे हुए थे। बावजूद इसके उन्होंने इस संकट की घड़ी में प्रदेश की 23 करोड़ जनता तक अपनी पहुंच बना कर हर जरूरतमंद को सभी सुविधाएं मुहैया करवाई। मुख्यमंत्री को हर गांव-हर कस्बे के प्रत्येक व्यक्ति को लेकर चिंता है, जिससे प्रतिदिन वे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और पुलिस अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित कर उन्हें लगातार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ और उनकी टीम-11 के अथक प्रयास का सकारात्मक परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के फैलने की गति कम रही। लेकिन दिल्ली से वापस आए तब्लीगी जमातियों के कारण अचानक कोरोना पाजीटिव के केस बढ़ने लगे। जिसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तब्लीगी जमातियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। यही नहीं, प्रदेश सरकार इन तब्लीगी जमातियों को कोरनटाइन कर रही है, इनके सैंपल ले रही है। जिससे इन्का इलाज शुरू किया जा सके। ■

यूपी में कोरोना वायरस से बचाव तथा लाकडाउन की अवधि में नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए

मुख्यमंत्री योगी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं की गई कार्रवाई

03 अप्रैल: कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं में पेंशन पाने वाले 86,71,781 लाभार्थियों को 871.4693 करोड़ रुपये की बड़ी सौगत दी है। उन्होंने एक क्लिक के जरिए प्रदेश के पेंशनरों को दो माह की एकमुश्त पेंशन उनके अकाउंट में भेज दिया है।

02 अप्रैल : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनीसेफ की तरफ से भेजे गए 34 और एनएचएम की तरफ से 38 काउंसलरों और विशेषज्ञों की मदद से आश्रयस्थलों व घरों पर अकेले मौजूद बड़े-बुजुर्गों की काउंसलिंग करने का निर्देश दिया।

यूपी के गरीबों, बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों व अशक्तों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खजाना खोल दिया है। इन सभी के खातों में प्रदेश सरकार 850 करोड़ रुपये भेजेगी। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों के लिए भी अब तक की सबसे बड़ी रकम की घोषणा की गई। मनरेगा मजदूरों को एक दिन में 611 करोड़ रुपये के भुगतान की घोषणा की गई है। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के 83 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

01 अप्रैल : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा 24.73 लाख परिवारों के लगभग 1.17 करोड़ गरीबों व मजदूरों को 78947 मी. टन अनाज मुफ्त दिया। इस वितरण में अंत्योदय कार्ड धारकों, नरेगा श्रमिकों, श्रम विभाग में रजिस्टर्ड श्रमिकों तथा नगर विकास विभाग के दिहाड़ी मजदूरों को निशुल्क राशन वितरण किया जाएगा। अप्रैल माह के द्वितीय चरण में दिनांक 15 अप्रैल से समस्त कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट की दर से निशुल्क राशन (चावल) दिया जाएगा । यदि कोई व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कस्बा या कॉलोनी को होम क्वॉरेंटाइन किया गया है तो उस तक होम डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

30 मार्च : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा योजना के तहत राज्य के 27.5 लाख श्रमिकों के बैंक खाते में सीधे 611 करोड़ रुपये भेजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्रा लिखा। जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में दूसरे राज्यों की पूरी हिफाजत रखा जा रहा है।

अन्य राज्य अपने यहां उत्तर प्रदेश के लोगों का भी ख्याल रखें। मुख्यमंत्री ने हिंदी भाषी राज्यों को हिंदी में तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों के मुख्यमंत्री को अंग्रेजी में पत्र लिखा है।

29 मार्च : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर मोहान टोल प्लाजा और आलमबाग चौराहे पर बाहर से आ रहे श्रमिकों और लोगों से बातचीत की। इसके साथ ही उनकी जांच के बाद उनके लिए भोजन, शुद्ध पानी, दवा उपलब्ध करवाई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाहरी राज्यों के कामगारों के लिए सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, जिससे उन्हें पलायन की जरूरत न पड़े।

मुख्यमंत्री ने कोरोना के चलते बंद हो गए उद्योगों को चलाए जाने का निर्णय लिया। इसके तहत उद्योंगों के कार्मिकों के पास आदि की व्यवस्था की गई। 1873 इकाईयों को चालू होनी थी। जिसमें 1425 इकाईयां चालू हो गई। 335 इकाईयों में कर्मचारियों के पास की समस्या है। जबकि 989 इकाईयों में पास की समस्या हल की गई है।

लॉकडाउन अवधि में ही 3541 इकाईयों द्वारा मजदूरों को भुगतान किया गया है। अब तक 5314 इकाईयों से बातचीत हुई। इसमें 2503 इकाईयां इस पर सहमत हुई। इसके साथ ही मजदूरों के भरण-पोषण के लिए 2163 इकाईयां अपने परिसरों में व्यवस्था कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मकान मालिक किसी कामगार या मजूदर से एक महीने का किराया नहीं लेगा। शिकायत मिलने पर पुलिस किराया लेने वाले मकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 30 एवं 31 मार्च को प्राइवेट एवं सरकारी कार्यालयों को खुलवाकर कर्मचारियों को एक माह का वेतन देने का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बाहर से आए लोगों को जनपद स्तर पर हर हालत में उनकी स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वॉरेंटाइन में रखे जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस लाइन में अतिरिक्त भोजन पैकेट बनवाएं जाएं, जिससे कहीं भी लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां बंटवाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में भारत सरकार के राहत पैकेज को अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आगे बढ़ाए जाने का निर्देश दिया।

28 मार्च : योगी सरकार ने किसानों के राहत के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद तय समय पर शुरू होगी। इस क्रम में सरसों, चना और मसूर की खरीद दो अप्रैल से शुरू होगी। खरीद के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त किये जा रहे हैं। मालुम हो कि सरकार एमएसपी पर क्रमशः 2.64 लाख मीट्रिक टन सरसों, 2.01 लाख मीट्रिक टन चना और 1.21 लाख मीट्रिक टन मसूर किसानों से खरीदेगी। ये खरीद 90 दिन तक होगी।

रबी के मौजूदा सीजन में फरवरी-मार्च का मौसम बेहद अप्रत्याशित रहा। भारी बारिश और ओला पड़ने से कई जगह किसानों की फसलों को क्षति पहुंची है। सरकार की मंशा है कि जिन किसानों की फसलों को क्षति पहुंची है उनको तय समय में अनिवार्य रूप से बीमित रकम मिले। इसके लिए सरकार ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे सर्वे कराकर तय समय में किसानों को उनकी क्षति की भरपाई करें। सभी जिलों के डीएम को यह निर्देश दिया गया है कि वह सर्वे के इस कार्य के लिए बीमा कंपनी के साथ कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को पास जारी कर दें। अब तक करीब 90 हजार किसानों के आवेदन बीमा कंपनियों के पास आ चुके हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के कारागारों में बंद करीब 11,000 बंदियों को 8 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा। इसमें 8500 विचाराधीन और 2500 सिद्धदोष बंदी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, लद्दाख के साथ दक्षिण में केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के साथ पूर्वोतर के राज्यों में भी नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। जो लोग दूसरे राज्यों में हैं, वहां कारोबार और नौकरी कर रहे हैं, वे नोडल अधिकारियों से संपर्क कर हर तरह की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

दिल्ली सहित अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के लोगों के नोएडा, गाजियाबाद हापुड़, बुलंदशहर और अलीगढ़ में पहुंचने की खबर मिलने पर मुख्यमंत्री योगी ने उनके लिए बसें लगवाई। सीएम ने रातों-रात 1000 बसें लगाकर पूरी जांच के बाद सभी यात्रियों को सकुशल उनके घर भेजने की व्यवस्था की।

27 मार्च : प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को, वे जहां हैं, वहीं किसी विद्यालय, धार्मिक स्थल, सामुदायिक केन्द्र आदि पर रोक कर, लाक डाउन की अवधि तक भोजन, पेयजल, दवा आदि अन्य सुविधाएं' उपलब्ध करायी जाएं।

केन्द्र सरकार की 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' की सुविधाएं प्रदेशवासियों को सुलभ कराने के लिए सम्बन्धित विभाग तुरन्त तैयारी प्रारम्भ कर दें।

मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र, हरियाणा तथा उत्तराखण्ड सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर उनके राज्यों में प्रदेश के निवासियों को सभी व्यवस्थाएं यथा स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के मूल निवासियों की दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को राज्यवार प्रभारी बनाया गया है।

लाक डाउन अवधि में किसानों की सुविधा के लिए बीज, उर्वरक तथा कृषि रक्षा रसायनों की दुकानों को खुला रखने के लिए शासनादेश जारी। जिला प्रशासन को हार्वेस्टर के लिए स्थानीय स्तर पर पास निर्गत करने के निर्देश।

प्रदेश के समस्त जनपदों में 18,772 वाहनों के माध्यम से नागरिकों को फल एवं सब्जी उपलब्ध करायी गयी। 8,41,332 लीटर दूध की बिक्री की गयी।

मुख्यमंत्री योगी ने 12 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली के लिए नोडल अफसर तैनात किए, जो संबंधित राज्यों के अधिकारियों से को-आर्डिनेट कर यूपी के नागरिकों को दिलाएंगे सभी सुविधाएं।

26 मार्च : मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारी संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करें। आमजन को आवश्यक वस्तुएं होम डिलीवरी व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएं। सीमावर्ती जनपदों के प्रशासन को प्रदेश के अन्दर आश्रय स्थलों, रैन बसेरों आदि स्थलों में रुके व्यक्तियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने के निर्देश अतिवृष्टि व ओलावृष्टि तथा लाकडाउन से अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव का आकलन तथा इससे निपटने के लिए रोडमैप बनाने हेतु अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन।

प्रमुख सचिव कृषि तथा प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को लाकडाउन की स्थिति में गेहूं और आलू की तैयार हो रही फसल के प्रोक्योरमेंट की कार्ययोजना बनाने के निर्देश।

सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से 60,000 से अधिक ग्राम पंचायतों से संवाद कर कोरोना से बचाव एवं इलाज की जानकारी देने के साथ ही, ग्राम पंचायतों में इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कोरोना लाक डाउन के दृष्टिगत प्रदेश के बार्डर पर आ रहे अन्य राज्यों को पैदल जाने वाले मजदूरों व कर्मकारों के लिए मानवीय आधार पर विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मानवीय आधार पर ऐसे व्यक्तियों के लिए भोजन व पानी

की व्यवस्था की जाए और स्वास्थ्य सम्बन्धी पूरी सावधानी बरतते हुए इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। बिहार जाने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इन्हें सुरक्षित उनके गन्तव्य तक भेजा जाएगा। उत्तराखण्ड निवासी सभी लोगों के भोजन व संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यथा स्थान ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया।

वाराणसी सहित प्रदेश के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर फंसे अन्य राज्यों यथा गुजरात आदि के तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन व सुरक्षा आदि की व्यवस्था न रहे। इसके लिए जिला प्रशासन कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन के साथ-साथ पेयजल की व्यवस्था करे।

24 मार्च : कोरोना पर नियंत्रण के लिए किये जा रहे प्रयासों एवं लाकडाउन की मानीटरिंग के लिए मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में 04 कमेटियां गठित।

मुख्यमंत्री की निर्णय को क्रियान्वित करने में दवा विक्रेता संगठनों व व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों से समर्थन व सहयोग की अपील। कोरोना वायरस से प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर तथा पीलीभीत शामिल। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्धसरकारी उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों, माल्स, दुकानों, फैक्ट्रियों, वर्कशाप, गोदामों एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा) आदि को लाकडाउन करने के निर्देश। स्वास्थ्य सम्बन्धी आकस्मिकता या आवश्यकता के लिए '102',

सुनिश्चित की जाए।

कोरोना को मात देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विभागों को जोड़कर 11 कमेटियां बनाई हैं। जिसमें सरकार के करीब दो दर्जन वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इनकी निगरानी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। कोरोना वायरस की जांच हेतु 08 टेस्टिंग लैब क्रियाशील।

विधायक निधि का उपयोग कोविड-19 के चिकित्सीय परीक्षण, स्क्रीनिंग एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु किये जाने के लिए निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन। इससे विधायकगण उपकरण, कोरोनो परीक्षण किट, आई0सी0यू0 वेंटिलेटर, आइसोलेशन/क्वारेन्टाइन वार्ड तथा चिकित्सा कर्मियों हेतु फेस मास्क, ग्लव्ज, सेनीटाइज़र की व्यवस्था हेतु निधि का उपयोग कर सकेंगे।

25 मार्च 2020 : मुख्यमंत्री के निर्देश पर 18 हजार से अधिक वाहन सब्जी, दूध, दवा व खाद्यान्न घर-घर पहुंचाने के लिए लगाए गए। यह सुनिश्चित किया जाए कि रैन बसेरों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे के बाहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी व्यक्ति भूखा-प्यासा संक्रमित मरीजों के लिए 11,000 अतिरिक्त आइसोलेशन बेड तैयार।

श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत 5 लाख 97 हजार निर्माण श्रमिकों के खातों में 01-01 हजार रुपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से आज हस्तांतरित। प्रतिदिन कमाने वालों को एक माह का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।

23 मार्च : मण्डी निदेशक को लाक डाउन जनपदों में दूध तथा सब्जी की सप्लाई चेन मुकम्मल करने के निर्देश। अधिकारियों को अन्य आवश्यक वस्तुओं तथा दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश।

उत्तर प्रदेश की सभी अंतर्राज्जीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से सील करने के निर्देश।

22 मार्च 2020 : मुख्यमंत्री जी ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश के 16 जनपदों को 23 से 25 मार्च, 2020 तक लाकडाउन करने के निर्देश दिए। इसमें लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, '108' और एएलएस का प्रयोग किया जाए। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों पर पहुंचने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के लिए पर्याप्त संख्या में थर्मल स्कैनरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

21 मार्च : मुख्यमंत्री योगी ने दैनिक रूप से कार्य करके अपने व अपने परिवार का जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के सहायतार्थ अनेक निर्णय लिए। श्रम विभाग के 20.37 लाख पंजीकृत श्रमिकों को 'लेबर सेस फण्ड' से प्रत्येक श्रमिक को 1000 रुपए प्रति माह डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था। नगर विकास विभाग को घुमन्तु प्रकृति जैसे ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि से जुड़े लगभग 15 लाख श्रमिकों का डेटाबेस सहित विवरण 15 दिन में तैयार करने के निर्देश, ऐसे सभी श्रमिकों के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में बन्द शैक्षणिक संस्थानों, माल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरण ताल, रेस्टोरेन्ट आदि के कारण प्रभावित श्रमिकों/कार्मिकों के हित के दृष्टिगत

बन्द इकाईयों के स्वामियों/नियोजकों से अपील की कि प्रभावित श्रमिकों/कार्मिकों को इकाईयों की बन्दी अवधि में सभुगतान अवकाश प्रदान किया जाए।

लगभग 1 करोड़ 65 लाख अन्त्योदय योजना, मनरेगा तथा श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं दिहाड़ी मजदूरों को 01 माह का निःशुल्क राशन अप्रैल 2020 में उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न पेंशन योजनाओं के 83.83 लाख लाभार्थियों को दो माह की अग्रिम पेंशन अप्रैल माह पेंशन दी जाएगी।

पुलिस को पूरे प्रदेश में व्यापक पेट्रोलिंग करने के निर्देश, लोग कहीं इकट्ठा न हों। तहसील दिवस, समाधान दिवस, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला तथा जनता दर्शन 2 अप्रैल, 2020 तक स्थगित। 31 मार्च, 2020 तक सरकारी अस्पतालों में गैर-जरुरी ओपीडी व जांच स्थगित, केवल आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी

19 मार्च 2020 : धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ न इकट्ठी हो, इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी ने धर्म गुरुओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता का

निर्देश दिये।

15 मार्च : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों के सन्दर्भ में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की। प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में कोरोना वायरस से बचाव के सम्बन्ध में समयबद्ध ढंग से पूरी तैयारी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश। जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपने जनपद के जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड0 तथा ओपीडी में पृथक से

ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगर निकायों के असहाय व्यक्ति जिनके पास अपने व अपने परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं है ऐसे व्यक्तियों को जिलाधिकारी द्वारा समिति की संस्तुति पर 1000 रुपए प्रतिमाह उपलब्ध कराए जाएंगे।

मेट्रो रेल सेवा सहित परिवहन निगम तथा नगर विकास विभाग की सभी बस सेवाएं प्रातः 06 से रात्रि 10 बजे तक बन्द रहेंगी।

20 मार्च 2020 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, नोएडा और कानपुर शहर को सैनिटाइज़ करने के निर्देश दिए। धर्माचार्यों एवं धर्मगुरुओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की अपील। सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियों/कार्यक्रमों को 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित कर दें।माल्स को बन्द करने के निर्देश। जिलाधिकारियों के निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी न होने पाए।

प्रसार करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आमजन से अनुरोध किया कि चैत्र नवरात्रि में लोग अपने घर में ही रहकर धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न करें। एसडीआरएफ शहरों में इस बीमारी की रोकथाम में जनता को सहयोग प्रदान करें।

17 मार्च 2020 : दिहाड़ी मजदूरों के भरण-पोषण के लिए निश्चित धनराशि मुहैया कराने के उद्देश्य से वित्तमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित। सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले के धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों और धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोरोना के प्रति लोगों को जागरुक करने के निर्देश। निजी और सरकारी कर्मचारियों को बायोमैट्रिक हाजिरी से छूट।

16 मार्च : मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य भवन परिसर में स्थित राज्य संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने महामारियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक स्थायी और विस्तृत 'स्टेट आफ दि आर्ट' कण्ट्रोल रूम स्थापित करने के

स्थापित फीवर/फ्लू कार्नर का निरीक्षण करना सुनिश्चित करने के निर्देश। जिलाधिकारी अपने जनपद में कोरोना वायरस के रोकथाम, बचाव एवं उपचार से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों के नोडल अधिकारी बनाए गए।

13 मार्च : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम सम्बन्धी एक उच्चस्तरीय बैठक की। चिकित्सकों, पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ आदि के प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रम सुनिश्चित किये गये हैं। पंचायतीराज, ग्राम्य विकास तथा नगर विकास विभाग को व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए। बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षा के सभी विद्यालयों और कौशल विकास से जुड़े सभी संस्थानों को बन्द करने के निर्देश। भारत-नेपाल सीमा के सभी चेक पोस्टों पर थर्मल एनालाइजर स्थापित किये गये। प्रदेश के सभी हवाई अड्डो पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था। जनपदों में कोरोना फ्लू से निपटने के लिए कण्ट्रोल रूम स्थापित। ■

मौत के सौदागर तब्लीग़ियों पर किस-किसकी नजरें नरम

✍ आर.के. सिन्हा

कोरोना वायरस के रास्ते मौत के मुंह में झोंकने की कथित रूप से साजिश करने वाले तब्लीग़ी जमात का अगर आज देश में इतना लंबा-चौड़ा जाल बिछ गया तो इसके पीछे बहुत से सियासी नेताओं और सरकारी अफसरों का भी हाथ अवश्य ही रहा है। तब्लीग़ी जमात तो कतई विशुद्ध धार्मिक संगठन नहीं है। अगर तब्लीग़ी जमात को कठघरे में खड़ा किया जा रहा है तो इसकी ठोस वजहें भी हैं। वर्ना इससे किसी की भी कोई निजी खुंदक क्यों होगी?

एक मिनट के लिए तब्लीग़ी जमात की हालिया हरकत की बात नहीं करते, जिसके कारण सारे देश में कोरोना वायरस के रोगियों का आंकड़ा अचानक बढ़ गया है। उनमें से कई की मौत भी हो चुकी है। ये सब बेशक दुखद भी है और शर्मनाक भी। पर एक सवाल पूछने का मन कर रहा है कि राजधानी के अति महत्वपूर्ण इलाके निजामुद्दीन में तब्लीग़ी जमात का मरकज यानी मुख्यालय बनने किसने दिया? अगर आपने इस मरकज की इमारत देखी हो तो आप खुद कहेंगे कि ये मेनरोड से भी आगे बढ़ी चली जा रही है। यह बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में लगभग दो हजार वर्गमीटर के प्लॉट पर खड़ी है। इसमें दो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर के अतिरिक्त छह ऊपरी मंजिलें भी हैं, जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है, जहां हजारों जमात कार्यकर्ताओं के रहने की व्यवस्था होती है और प्रतिदिन हजारों लोगों का आना-जाना रहता है। प्रख्यात वकील और मुस्लिम सहर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री मसरूर हसन सिद्दिक़ी कहते हैं, वर्ष 1992 में मरकज की ढाई मंज़िल इमारत बनाने का नक्शा दिल्ली नगर निगम से पास हुआ था। मरकज का नहीं एक मदरसे का।÷ लेकिन 1995 के आते-आते दो बेसमेंट और छह ऊपरी तल के साथ आलीशान इमारत कैसे बन जाती है। कैसे? यह मुमकिन हुआ होगा राजनीतिक असर और प्रभाव का इस्तेमाल करके, पुलिस, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली फायर सर्विस और लोकल लोगों की मिलीभगत से ही।÷

गौर करें कि तब्लीग़ी जमात मुख्यालय से सटे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) के कई संरक्षित स्मारकें। उनमें चौंसठ खंबा स्मारक भी है। यह 1623-24 के दौरान बनाया गया एक मकबरा है। इसके नाम से ही साफ '64 स्तंभ' है। इसे उस समय बनाया गया था जब मुगल सम्राट जहाँगीर ने दिल्ली पर शासन किया था। तो कायदे से एएसआई की तरफ से संरक्षित इस तरह के स्मारक के 100 मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता था। लेकिन मरकज की बिल्डिंग बन जाती है। कैसे? जाहिर है कि यह बिना सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार के खड़ी नहीं हो सकती थी। यह भी पता करना होगा कि मरकज के प्रबंधन ने नियमानुसार एएसआई की अनुमति ली थी कि नहीं। यदि यह अनुमति नहीं ली तो ढाई मंजिली इमारत का नक्शा कैसा पास हो गया?

क्या सरकारी अफसरों पर आरोप लगाते हुए हम उस दौर की सरकार

और राजनेताओं को माफ कर दें जिनके आशीर्वाद से यह बनी। बेशक नहीं। सवाल और भी हैं। पिछले साल दिल्ली के करोलबाग में अर्पित पैलेस होटल में आग लगी थी। उसमें बहुत से लोगों की जानें चली गई थीं। सारी दिल्ली दहल गई थी उस अग्निकांड से। तब दिल्ली अग्निशमन विभाग ने राजधानी के सभी होटलों, गेस्ट हाउसों तथा धर्मशालाओं, जहां मुसाफिर रुकते हैं, उनका निरीक्षण किया और आग व आपात स्थिति से निपटने के इंतजाम करने के लिए कहा। उसने ये भी निर्देश दिए कि अनाधिकृत ऊपरी मंज़िल, जो 15 मीटर ऊंचाई से ज़्यादा है, उसे तुरंत हटा लिया जाए। क्या तब्लीग़ी जमात की मरकज का ऐसा कोई निरीक्षण पुलिस, नगर निगम, दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने किया? यदि किया तो मरकज ने क्या कारवाई की! इन सवालों के जवाब तो मौलाना साद को देने ही होंगे।

जहां मरकज की बिल्डिंग है, वह रास्ता बहुत ही संकरा है और आग या अन्य आपदा के समय बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है क्योंकि अग्निशमन गाड़ियाँ वहां मुश्किल से ही पहुंचेगी। इससे चंद कदमों की दूरी पर हजरत निजामउद्दीन और अमीर खुसरो की दरगाहें और गालिब अकादमी भी हैं। इधर भी हर रोज बहुत से लोग आते-जाते हैं।

क्यों न शिफ्ट हो मरकज

इन हालातों में क्या तब्लीग़ी जमात के हेडक्वार्टर को किसी बड़ी खुली जगह शिफ्ट नहीं कर लेना चाहिए या जहां सबकुछ ठीक तरह से हो, कोई क़ानून की अवहेलना न हो और सब सुरक्षित रहें? चूंकि कोरोना वायरस को फैलाने में तब्लीग़ी जमात की भूमिका साफ नजर आ रही है, इस लिए अब उसके अध्यक्ष मोहम्मद साद से इतनी अपेक्षा तो कोई भी करेगा कि वे खुद सरकार और प्रशासन से कहें कि वे मरकज की इमारत को कहीं और शिफ्ट करने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि तब्लीग़ी जमात को उसके अपराध और पाप की सजा न दी जाये। अभीतक जिस जमीन पर मरकज की सात मंजिली इमारत खड़ी है, उससे संबंधित कोई कागज और पास नक़्शे की कॉपी भी नहीं मिली है। इससे यह शक तेजी से यकीन में बदलता जा रहा है कि मरकज अवैध सरकारी जमीन पर खड़ी है।

एक बात साफ करना चाहता हूं कि देश में मुसलमानों के बहुत से अन्य संगठन सक्रिय हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना ठोस और रचनात्मक योगदान भी दे रहे हैं। उनमें मुंबई का अंजुमन-ए-इस्लाम और बोहरा मुसलमानों के तमाम संस्थान, लखनऊ के कई शिया संगठन शामिल हैं। मुंबई में अंजुमन-ए-इस्लाम के बहुत से स्कूल-कॉलेज हैं। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार और दिग्गज क्रिकेटर वासिम जाफर ने अपनी पढाई यहीं से की है। इसी तरह से दिल्ली में यतीम बच्चों को शिक्षा देने और बेहतर नागरिक बनाने के लिए लिए दरियागंज में 'बच्चों का घर' नाम की संस्था भी उल्लेखनीय कार्य कर रही है। उसने अपने 100 सालों का सफर भी पूरा कर लिया है। इन जैसे मुस्लिम संगठनों पर तो कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। तब्लीग़ी जमात इसलिए निशाने पर है क्योंकि उसकी गतिविधियां संदिग्ध और शर्मनाक रही हैं। ये संगठन मानवता के नाम पर कलंक है।

बहरहाल, बात ये है कि जब तब्लीग़ी जमात की काली करतूतों का काला चिट्ठा खुले तो उन राजनेताओं और स्थानीय निकाय के बाबुओं को भी छोड़ा न जाए जिन्होंने तब्लीग़ी जमात को अपना खुला खेल खेलने की अनुमति दी। अगर कोई सरकारी बाबू, भले ही वह आज के दिन रिटायर हो गया हो, उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य मिलते हैं तो उसकी पेंशन रोक दी जाए। फिर उसके खिलाफ केस चले। वे भी जेल की हवा खायें। इसी तरह से उन राजनेताओं के नाम भी जाहिर होने चाहिए जो तब्लीग़ी जमात को बेशर्मी के साथ संरक्षण देते रहे हैं। ■

(लेखक वरिष्ठ संपादक एवं स्तंभकार हैं।)

आत्मघाती तब्लीग़ी जमात से संकट में देश

✍ विकास सक्सेना

कोरोना महामारी से बचाव के प्रयासों को तब्लीगी जमात के आत्मघाती कदम से भारी क्षति पहुंची है। जमातियों ने चिकित्सकों और मेडिकल कर्मचारियों के साथ अमानवीय तथा अश्लील व्यवहार करके पूरी मानवता को शर्मसार किया है। इसके बावजूद एक वर्ग इनका बचाव करने के लिए कुतर्क गढ़ रहा है। लोगों से मस्जिदों में इकट्ठा होने की अपील करने वाला जो मौलाना मुसलमानों से कह रहा था कि मरने के लिए सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, वह खुद पुलिस कार्रवाई के डर से छिपा बैठा है। जमातियों की करतूतों को देखकर एक बड़े वर्ग को यह विश्वास हो गया है कि देश में कोरोना महामारी को फैलाने के लिए सोची-समझी साजिश के तहत यह किया गया।

सम्पूर्ण मानवजाति के अस्तित्व के लिए चुनौती बन चुके कोरोना वायरस का जन्म चीन में हुआ। इटली और स्पेन में पल बढ़कर यह अमरीका में जवान हुआ और भारत तक पहुंच गया। शुरुआत में एक वर्ग में इसे लेकर तरह-तरह की अफवाह उड़ायी गयी। इससे जुड़ी भ्रांतियां फैलाने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किए गए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे शाहीन बाग सरीखे आंदोलनों को बनाए रखने के लिए इसका जमकर इस्तेमाल किया गया। लेकिन इन आंदोलनों को अंततः सख्ती से खत्म कराया गया। हैरानी की बात यह है कि इन भ्रांतियों के बीच लोग यह भी समझने को तैयार नहीं थे कि इस्लामिक राष्ट्रों पाकिस्तान, ईरान और सउदी अरब में कोरोना का लगातार फैलाव हो रहा है। मक्का और मदीना के बंद हो जाने के बावजूद भारत में ये अपनी मस्जिदों को ''आबाद'' रखने की खुदकश जिद पर अड़े रहे। खासी मशक्कत के बाद पुलिस और प्रशासन ने इन लोगों को घरों के भीतर भेजा।

तब्लीगी जमात के कार्यक्रम का मामला पहली बार 30 मार्च को जब मीडिया की सुर्खियां बना तो लगा कि जमात के लोग इस वायरस के संक्रमण की गंभीरता को शायद समझ नहीं सके इसीलिए उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं किया। इसके बाद कुछ जमाती लॉकडाउन होने के कारण निजामुद्दीन मरकज में फंस गए। पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना न देने के भी कारण समझ में आते हैं कि जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशी पर्यटक वीजा पर भारत आते हैं। कानूनन ये लोग किसी तरह का धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जमात का तो मुख्य काम ही लोगों के बीच इस्लाम का प्रचार-प्रसार करना है। इसलिए विदेशों से आए हुए जमाती पूरे देश की

मस्जिदों में फैल जाते हैं और वहां अपने तरीके के इस्लाम का प्रचार करते हैं। इस्लाम के प्रचार में जुटे टूरिस्ट वीजा पर भारत भ्रमण पर आए जमातियों को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई।

शुरुआती दौर में एक बड़े वर्ग, जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल थे उनका मानना था कि तब्लीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में लोग अनजाने या भूलवश फंस गए थे। लेकिन जमात से जुड़े लोगों की करतूतें मीडिया के जरिए जिस तरह लोगों के सामने आ रही हैं उससे विश्वास होने लगा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को सामुदायिक स्तर पर फैलाने के लिए सोची-समझी साजिश के तहत तब्लीगी जमात ने लोगों को संक्रमित कर देश के विभिन्न हिस्सों में छिपा दिया। भारी मशक्कत के बाद इन लोगों को ढूंढकर निकाला गया। एकांतवास में रखे गए संदिग्ध और उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती कराए गए जमातियों की हरकतें मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। ये लोग सुरक्षाकर्मियों, चिकित्सकों और दूसरे कर्मचारियों को संक्रमित करने के लिए उनके ऊपर तथा खुले में लगातार थूक रहे हैं, उनके सामने जानबूझकर जोर-जोर से खांस रहे हैं। इसके अलावा बेशर्मी से महिला नर्सों और चिकित्सकों के सामने अश्लील हरकतें कर रहे हैं। इन लोगों की अमानवीय करतूतों से परेशान उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जमातियों के उपचार एवं देखभाल में महिला चिकित्सकों और नर्सों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। सरकार के इस फैसले की मानवीय आधार पर कुछ लोग आलोचना भी कर सकते हैं लेकिन उन्हें समझना होगा कि मारपीट और अश्लीलता करके मानवता को शर्मसार करने वाले मानवाधिकार के पात्र नहीं हो सकते।

सरकार के हर कदम का विरोध करने और उसकी हर कोशिश को किसी भी कीमत पर नाकाम करने की जुगत में लगे रहने वाला एक वर्ग तब्लीगी जमात और उसके मुखिया मौलाना साद की पैरोकारी में उतर आया है। पहले तो वे निजामुद्दीन मरकज में प्रतिबंध के बावजूद हजारों लोगों की भीड़ जुटने को गलत मानने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन अब दबी जुबान में इसे अनजाने में हुई गलती स्वीकार करने लगे हैं। लेकिन इन लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जब तेलंगाना में जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए छह लोगों की मौत के बाद साफ हो गया था कि इसमें शामिल हुए लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है तो तब्लीगी जमात के प्रबंधकों ने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों के नाम, पते और मोबाइल नम्बर या दूसरे कान्टैक्ट नम्बर प्रशासन को उपलब्ध क्यों नहीं कराए? इस तरह कार्यक्रम में शामिल लोगों को क्वारंटीन करके कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को रोका जा सकता था। इसके अलावा मौलाना साद को अपने अनुयायियों से कहना चाहिए कि वे स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें। इसके उलट जमाती न सिर्फ छिप गए बल्कि उन्होंने जांच का भी विरोध किया।

कोरोना वायरस के खिलाफ महायुद्ध में बेहतर स्थिति में पहुंच रहे भारत को तब्लीगी जमात के लोगों की करतूतों ने बड़े संघर्ष की तरफ धकेल दिया है। मौलाना साद के हिमायती तब्लीग़ी जमात की आलोचना को मुसलमानों के खिलाफ साजिश की तरह पेश कर रहे हैं ताकि वे मुसलमानों की हमदर्दी की आड़ में छिपकर खुद को सुरक्षित कर सकें। लेकिन हकीकत यह है कि जमातियों की करतूतों का सबसे बड़ा नुकसान आम मुसलमानों को ही उठाना पड़ा है। निजामुद्दीन मरकज से संक्रमित होकर देशभर की मस्जिदों में पहुंचे जमातियों ने आम मुसलमानों को कोरोना संक्रमित करके उनके जीवन को संकट में डाला है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों से अश्लील हरकत करके उन्होंने देश-दुनिया के सामने जो तस्वीर पेश की है वो हर मुसलमान के लिए शर्मसार करने वाली हैं। इसलिए मुसलमान भी खुलकर इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। ■

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

और भी हैं मरकज मामले में गुनहगार

✍ डॉ. रमेश ठाकुर

तब्लीगी जमात मामले में फिलहाल दिल्ली की अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में मौलाना साद मुख्य आरोपी हैं, होने भी चाहिए क्योंकि मुख्य हिमाकत उन्हीं के द्वारा हुई। सबकुछ जानते हुए भी कईयों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। लेकिन, मरकज मामले में सिर्फ मौलाना साद ही गुनाहगार नहीं हैं बल्कि कई और भी हिस्सेदार हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस-प्रशासन भी उतने की जिम्मेदार हैं जितने मौलाना साद हैं। इनके अलावा प्रदेश सरकार भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से संल्पित दिखाई पड़ती है। दरअसल, निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी जमात का मरकज यानी इस्लामिक धार्मिक आयोजन दिल्ली सरकार की स्वीकृति पर ही आयोजित हुआ।

सवाल उठता है कोरोना के कहर के बीच दिल्ली सरकार ने मरकजी के सालाना जलसे को इजाजत दी क्यों? अगर इजाजत देनी थी तो दूसरे मुल्कों से आने लोगों की ठीक से जांच क्यों नहीं की गई। साथ ही पूरे मामले से केंद्र सरकार को अवगत क्यों नहीं कराया? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है। खैर, मामला अब एक्सपोज हो ही चुका है तो देखने वाली बात यही होगी कि गलती किसकी और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस्लामिक धार्मिक मरकज से जो पूरे हिंदुस्तान की मुस्किलें बढ़ी हैं वह जल्द कम होने वाली नहीं। बेखबर और बेपरवाह जमातियों ने एक नहीं बल्कि 11 राज्यों को मुश्किल में डाल दिया। तब्लीगी जमात में शामिल लोग दिल्ली के बाद कई राज्यों में गए, जहां-जहां गए वहां के लोग भयंकर दहशत में हैं।मालूम हो, पहली से लेकर पंद्रह मार्च के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तब्लीगी जमात के मरकज में करीब पांच हजार लोग विभिन्न देशों के शामिल हुए थे। कार्यक्रम पहले से तय था ये तो नहीं पता।

पर, ये इस्लामिक धार्मिक आयोजन उस वक्त हुआ जब समूचा संसार कोरोना त्रासदी से बेहाल है। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पांच हजार में करीब तीन हजार लोग हिंदुस्तान के विभिन्न जगहों पर घूमने और अपने रिश्तेदारों से मिलने गए और दो हजार के आसपास लोग मरकज भवन में ही रुके रहे। लॉकडाउन हो जाने के चलते ये लोग निकल नहीं पाए। इन्हीं में एकाध लोग पहले से कोरोना पीड़ित थे, पर उन्हें शायद पता नहीं था। उनके संक्रमण से धीरे-धीरे दूसरे लोग भी चपेट में आते गए। एहतियात के तौर पर भी किसी ने खुद से प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं दी। मरकज भवन में रहते रहे।पूरे मामले पर मौलाना साद भी चुप्पी साधे रहे। जबकि उनको आगे आकर राज्य सरकार को अवगत कराना चाहिए था। इसके अलावा लोकल पुलिस-प्रशासन भी कुंभकरण की नींद सोता रहा। उनके इलाके की एक बिल्डिंग में दो हजार लोग एकसाथ रह रहे हैं, वह भी विदेशी, फिर भी प्रशासन को खबर नहीं हुई। संभावनाएं ऐसी भी जताई गई हैं कि प्रशासन को भनक थी पर कान में रूई डाले बैठे रहे। इस लिहाज से मौलाना साद के अलावा ये सभी भी बराबर के गुनाहगार हैं। इनपर भी कानूनी कार्रवाई बनती है। केंद्र सरकार को पूरे मामले पर गंभीर होना होगा, जमात में शामिल होने वाले दूसरे मुल्कों के लोग पर्यटक वीजा पर भारत आए थे।

लेकिन वह सभी गैरकानूनी तरीके से धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। सरकार को इनके वीजों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाना चाहिए।बहरहाल, इस मसले को मजहबी और हिंदू-मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। मसला सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जमात में शामिल लोगों की लापरवाही के चलते हजारों-लाखों बेकसूर लोग परेशानी में पड़ गए हैं। तब्लीगी मरकज की घोर हिमाकत ने केंद्र सरकार के लॉकडाउन से परेशानी को कम करने के प्रयासों को भी गहरा धक्का दिया है। जमात में जुटे लोग हिंदुस्तान के कई शहरों में अब भी छिपे हुए हैं। उनको पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। 157 लोग यूपी में छिपे हैं। उनकी खोज में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी दिन-रात मस्जिदों और मदरसों की खाक छान रहे हैं। कुछ पकड़ में आए हैं, कई अब भी नदारद हैं। यूपी के बाराबंकी, बरेली, गोंडा, सीतापुर, बलरामपुर और रामपुर से कई दबोचे गए हैं। इन्हें मस्जिदों में मौलाओं ने पनाह दी हुई थी और पहचान छिपाकर रह रहे थे।

जमात में ज्यादातर किर्जिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान-ईराक, कुवैत, बांग्लादेश और दुबई के लोग शामिल हुए थे। इनमें से किसी एक ने भी यह कहकर वीजा नहीं लिया था कि उन्हें तब्लीगी मरकज के धार्मिक आयोजन में शामिल होना है, सभी झूठ बोलकर पर्यटक वीजा पर दिल्ली पहुंचे थे।शायद केंद्र सरकार को इस मसले की जांच में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि गुनाह का तरीका और गुनाह करने वाले सामने हैं। देखने वाली बात यही होगी, कार्रवाई के शिकंजे में किसे शामिल और किसे छोड़ा जाएगा। मरकज के आयोजक, शामिल होने वाले लोग, उनको शह देनी वाली जमात, स्थानीय सांसद, विधायक, पार्षद, पुलिस एसएचओ और प्रशासन के अधिकारी सभी समानरूपी आरोपी हैं। कार्रवाई भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। सभी ने सामूहिक रूप से देशवासियों के जीवन को खतरे में डालने का षड्यंत्र रचा है। पूरे मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से तत्कालिक कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है। दिल्ली पुलिस को एलजी की तरफ से दिशा-निर्देश मिलने के बाद तब्लीगी मरकज के मुख्य आयोजक मौलाना साद व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन सभी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। ■

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

कोरोना काल में त्राहिमाम करता विश्व और राह दिखाती भारतीय परम्परायें

✍ डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग

मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।।

आज बड़ा ही पुनीत पावन पर्व है, प्रभु श्रीराम का दिन, सम्पूर्ण विश्व की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली, सबसे विराट मानव सभ्यता का दिन।पर इन हजारों हजार साल में यह देश कितने टुकड़ों में बँट, आज कहाँ और किस हाल में आ खड़ा हुआ है ?

लेकिन यह भी सच है कि आज भी यह देश अपनी आस्थाओं और जड़ों से वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसा कि प्रभु श्रीराम के समय रहा होगा क्योंकि तब उनका इस धरा पर आगमन धर्म, कर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए हुआ और आज भी कुछ वैसी ही स्थिति देश के सामने हैं, असुर, विधर्मी भाँति भाँति से प्राणियों पर कहर ढा रहे हैं, जीवन रक्षक डाक्टरों, पुलिसकर्मियों पर थूक रहे हैं, पथ्थर फेंक रहे हैं, राजकर्म में विघ्न बाधाएं पैदा कर रहे हैं, गंदगी से सराबोर हैं और जल, वायु, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि खुद भी एक अदृश्य से कीटाणु से चौपट हो जाने वाले हैं और बाकी का भी सर्वनाश करेंगे।

पर अभी भी देर नहीं हुई है । लौट आओ जड़ों की ओर। क्योंकि गहराई में जाकर शान्ति से सोचोगे तो पाओगे कि सब यहीं के हैं , इसी धरती के जन्में, इसी माटी के पले बड़े और चार पांच पीढ़ी पहले कौन क्या था, ये पता करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। मध्य युग में पूरे यूरोप पे राज करने वाला रोम (इटली) नष्ट होने के कगार पे आ गया , मध्य पूर्व को अपने कदमो से रोंदने वाला ओस्मानिया साम्राज्य (ईरान , टर्की) अब घुटनो पर हैं , जिनके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटिश साम्राज्य के वारिस बर्मिघम पैलेस में कैद हैं, जो स्वयं को आधुनिक युग की सबसे बड़ी शक्ति समझते थे, उस रूस के बॉर्डर सील हैं, जिनके एक इशारे पर दुनिया के नक्शे बदल जाते हैं, जो पूरी दुनिया के अघोषित चौधरी हैं, उस अमेरिका में लॉक डाउन हैं और जो आने वाले समय में सबको निगल जाना चाहते थे,वो चीन, आज मुँह छिपाता फिर रहा है और सबकी गालियां खा रहा है।

एक जरा से परजीवी ने विश्व को घुटनो पर ला दिया? न एटम बम काम आ रहे न पेट्रो रिफाइनरी ना मिसाइलें ? मानव का सारा विकास एक छोटे से जीवाणु से सामना नहीं कर पा रहा ? क्या हुआ, निकल गयी हेकड़ी ? बस इतना ही कमाया था आपने इतने वर्षों में, कि एक छोटे से जीव ने सबको घरो में कैद कर दिया ? और जो नहीं मान रहा, सूरमां बना घूम रहा है, उसको कोई छूने को, कांधा देने को भी तैयार नहीं है।और सारे देश आशा भरी नज़रो से देख रहे हैं आज हमारे देश की तरफ, उस भारत की ओर जिसका सदियों से अपमान करते रहे, रोंदते रहे, लूटते रहे, लेकिन एक मामूली से जीव ने सबको उनकी औकात बता दी।

पर भारत जानता है, भारत का वीर सेनापति जानता है कि असल युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, सीमा पार के छद्म विरोधी ही नहीं, देश में बैठे जयचंदों से भी और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियरो की बर्फ पिघलेगी, आज़ाद होंगे लाखो वर्षो से बर्फ की चादर में कैद दानवीय विषाणु, जिनका न आपको परिचय है और न लड़ने की कोई तेयारी, ये कोरोना तो झांकी है, चेतावनी है, उस आने वाली विपदा की, जिसे आपने जन्म दिया है। मेनचेस्टर की औध्योगिक क्रांति और हारवर्ड की इकोनॉमिक्स संसार को अंत के मुहाने पर आखिरकार ले ही आई है।

लेकिन क्या आप जानते हैं, इस आपदा से लड़ने का तरीका कहाँ छुपा है? तक्षशिला के खंडहरो में, नालंदा की राख में, शारदा पीठ के अवशेषों में, मार्तण्ड के पत्थरो में।सूक्ष्म परजीवियों से मनुष्य का युद्ध नया नहीं है, ये तो सृष्टि के आरम्भ से अनवरत चल रहा है, और सदैव चलता रहेगा, इस से लड़ने के लिए हमने हरेक का हथियार भी खोज लिया था, मगर आपके अहंकार, लालच , स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की हठ धर्मिता ने सब नष्ट कर दिया ।

क्या चाहिए था आपको ? स्वर्ण एवं रत्नो के भंडार? यूँ ही मांग लेते, राजा बलि के वंशज और कर्ण के अनुयायी आपको यूँ ही दान में दे देते। सांसारिक वैभव को त्यागकर आंतरिक शांति की खोज करने वाले समाज के लिए वे सब यूँ भी मूल्य हीन ही थे, ले जाते। मगर आपने ये क्या किया, विश्व बंधुत्व की बात करने वाले समाज को नष्ट कर दिया? जिस बर्बर का मन आया वही भारत चला आया, रोदने, लूटने, मारने, जीव में शिव को देखने वाले समाज को नष्ट करने।

कोई विश्व विजेता बनने के लिए तक्षशिला को तोड़ कर चला गया, कोई सोने की चमक में अँधा होकर सोमनाथ लूट कर ले गया, तो कोई खुद को ऊँचा दिखाने के लिए नालंदा की किताबो को जला गया, किसी ने बर्बरता को जिताने के लिए शारदा पीठ के टुकड़े टुकड़े कर दिये, तो किसी ने अपने झंडे को ऊंचा दिखाने के लिए विश्व कल्याण का केंद्र बने गुरुकुल परंपरा को ही नष्ट कर दिया और आज करुणा भरी निगाहों से देख रहे हैं उसी पराजित, अपमानित, पद दलित, भारत भूमि की ओर, जिसने अभी अभी अपने घावों को भर, अंगड़ाई लेना आरम्भ किया है।

किन्तु, ये देश और हम फिर भी निराश नहीं करेंगे, फिर से माँ भारती का आँचल आपको इस संकट की घडी में छाँव देगा, श्रीराम के वंशज इस दानव से भी लड़ लेंगे।

जिसके लिए कभी हमारे मस्तक धड़ से अलग किये थे । यही है प्रकृति का न्याय और आपको स्वीकारना होगा।

फिर कहता हूँ , इस दुनिया को अगर जीना है, तो केदार काशी, सोमनाथ में सर झुकाने आना ही होगा, तक्षशिला के खंडहरो से माफ़ी मांगनी ही होगी, नालंदा की ख़ाक छाननी ही होगी। मंदिरों के घंटानाद से तीव्र साउंड फ्रिकवेंसी से कई वायरस मर जाते हैं। और यह आपने स्वीकार करना प्रारंभ भी कर दिया है। हाथ जोड़कर अभिवादन करना भी सम्पूर्ण विश्व ने शुरू कर ही दिया है। बहुत जल्द ही भारत की छांव में पूरी तरह सबको आना ही होगा क्योंकि इस देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को मजबूर नहीं किया धर्म बदलने को, कभी किसी के गले नहीं काटे, मासूम बच्चों को तड़पा तड़पा कर नहीं मारा और ना ही कभी किसी के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार कब्जा किया ।

क्योंकि तब भी हमारा यही सिद्धांत था और आज भी यही है। इस देश का ब्रह्मवाक्य

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत्।। ■

कोरोना महा संकट : अंध विश्वास का नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें

✍ तनवीर जाफ़री

कोरोना महामारी ने पूरे विश्व के समक्ष एक ऐतिहासिक संकट खड़ा कर दिया है। विश्व के अमेरिका,चीन, इटली, तथा फ़्रांस जैसे अनेक संपन्न व विकसित देश इस भयंकर वॉयरस से निपट पाने में पूरी तरह से असहाय नज़र आ रहे हैं। इस महामारी ने न केवल लोगों के अस्तित्व के सामने संकट खड़ा कर दिया है बल्कि यह वैश्विक अर्थ व्यवस्था को भी तबाही की कगार पर ले आया है। परन्तु नित्य नये वैज्ञानिक शोध करने वाला इंसान अभी भी हारा नहीं है। पूरी दुनिया इस समय इस प्रलयकारी बीमारी से मुक़ाबला करने का इलाज खोजने में जुटी हुई है। ज़ाहिर है इस महासंकट के समय आम लोगों को भी न केवल पूरे धैर्य व संयम से काम लेने की ज़रुरत है बल्कि स्वयं को अंध विश्वास और किसी भी तरह की टोटकेबाज़ी से दूर रहते हुए इस संबंध में बनाए जा रहे सरकारी नियम व क़ायदे क़ानूनों का पालन करने की भी आवश्यकता है।

हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं देश की जनसंख्या के अनुपात में कितनी प्रभावी व कारगर हैं यह हम सभी भली भांति जानते हैं । कोरोना महामारी तो आज की बात ठहरी, हम तो लगभग प्रत्येक वर्ष इसी भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की अक्षमता के चलते लोगों की विशेषकर अपने नौनिहालों की सामूहिक मौतों की ख़बरें सुनते रहते हैं। हमारे देश में कभी चंकी बुख़ार तो कभी कालाज़ार, कभी इंसेफ़लाइटिस तो कभी जापानी बुख़ार, कभी ऑक्सीजन की कमी तो कभी अस्पतालों में डॉक्टर्स व बेड या वेंटिलेटर्स का अभाव अक्सर ही मासूमों की जान लेता रहता है। और हमारे देश की निम्नतर स्तर की होती जा रही राजनीति स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारु,कारगर, आधुनिक व पर्याप्त बनाने के बजाए कभी हमें धर्म जाति के झगड़ों में उलझा देती है तो कभी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे तमाम भावनात्मक मुद्दे उछाल देती है। हमारे देश में सरकार की प्राथमिकताएं भी स्कूल व अस्पताल से ज़्यादा पार्क निर्माण, नेताओं की मूर्तियों व स्टेचू बनाने, तथा अपने साम्प्रदायिक व जातीय एजेंडे पर चलते हुए अपने वोट बैंक की राजनीति करने की होती है। सरकार की प्राथमिकताएं में कभी अपने अस्पतालों का देश की जनसँख्या के अनुरूप विस्तार करने व आधुनिक शोध के बल पर देश को दुनिया के आधुनकतम स्वास्थ्य सेवाओं वाले देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने की कभी नहीं रही।

और ऐसा हो भी क्यों? जब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इस बात का विश्वास हो कि भारत में कोरोना का कोई असर नहीं होगा क्योंकि यहां 33 करोड़ देवी-देवता रहते हैं। विजयवर्गीय के अनुसार -कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि हमारे यहां जो हनुमान हैं उनका नाम मैंने कोरोना पछाड़ हनुमान रख दिया है । जब गौमूत्र और हवन के द्वारा,और अल्लाह ने यह बीमारी भेजी है काफिरो को ख़तम करने के लिए जैसी बातें और इसी प्रकार के तरह-तरह के निरर्थक नुस्ख़ों के द्वारा कोरोना का मुक़ाबला करने के उपाय ढूंढें जाने लगें तो हमारा ध्यान देश की वास्तविक स्वास्थ्य समस्याओं के तरफ़ से हटना स्वभाविक है। आज कहीं बेवक़्त लोगों के घरों से अज़ान की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अनेक लोग सरकार की विश्वव्यापी सोशल डिस्टेंसिंग नीति का पालन करने से ज़्यादा अपने घरों पर दुआ ताबीज़ लटका कर कोरोना पर फ़तेह हासिल करने की ग़लतफ़हमी पाले हुए हैं। कुछ का तो मन्ना है की मस्जिदों में सामूहिक नवाज़ पढ़ने से कोरोना उनको छुए गा नहीं।

परन्तु ऐसी विपरीत व दुर्गम परस्थितियों के बीच जबकि न केवल देश की स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा चरमराया हुआ है, बल्कि स्वयं डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मियों के पास उनकी अपनी सुरक्षा के पर्याप्त साधन व सामान भी नहीं हैं। उसके बावजूद डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मियों अपनी जान को ज़ोख़िम में डालकर हमें अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। देश में ऐसी कई ख़बरें आ चुकी हैं कि डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ की चपेट में आकर स्वयं इसी मर्ज़ का शिकार हो गए। ज़रा सोचिये कि इस मर्ज़ से प्रभावित होने की ख़बर सुनकर जब आपके सगे संबंधी आपसी फ़ासला बनाना बेहतर समझें,जब आपका पड़ोसी और मुहल्ले के लोग आपकी कोरोना पॉज़िटिव होने की ख़बर सुनकर आपका घर या मोहल्ले में रहना ही पसंद न करें। यहाँ तक कि ख़ुद क़ब्रिस्तान कमेटी के लोग कोरोना से हुई मौत वाले शख़्स की लाश को दफ़नाने तक से इंकार करदें। ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि डॉक्टर्स, नर्सेज़ या अन्य स्वास्थ्य कर्मी आपकी जान बचाने का ज़ोख़िम उठा

रहे हों तो क्या वे किसी अल्लाह, भगवान या देवदूत से कम हैं ? पूरे देश को एकजुट होकर सलाम करना चाहिए इस देश के जांबाज़ डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मियों को।

बड़े अफ़सोस की बात है कि देश के कई भागों से इन्हीं फ़रिश्ता रुपी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले व इनसे दुर्व्यवहार करने की ख़बरें सुनाई दे रही हैं। आज जो लोग अति सीमित संसाधनों के बीच अपनी जान को ख़तरे में डालकर तथा अपने परिवार का मोह छोड़कर दिन रात एक कर देश को इस महामारी के संकट से बचाने की जद्दोजेहद में लगे हैं उन्हें न केवल सम्मान दिए जाने की ज़रुरत है बल्कि उनका हौसला बढ़ाने व उनके साथ पूरा सहयोग किये जाने की भी ज़रुरत है। आप थाली बजाएं,ताली बजाएं,शंख,घंटी, घंटा कुछ भी बजाएं। बत्ती जलाएं-बुझाएं,अज़ान दें घरों में नमाज़ अदा करें मन्त्रों का जाप करें ,जो चाहे करें परन्तु अपनी वैज्ञानिक सोच को ज़रूर कायम रखें क्योंकि यही वह सच्चाई है जो इस समय समूची मानव जाति को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। डॉक्टर्स,नर्सेज़ व स्वास्थ्य कर्मियों में ही देवता व फरिश्तों का रूप देखें। फ़ारसी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मौलाना मुहम्मद जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है कि - %एक बार तेज़ आंधी चल रही थी और एक शख़्स एक दरख़्त के नीचे खड़ा अल्लाह को याद कर रहा था। उधर से एक राहगीर गुज़रा और उस शख़्स से कहा कि इस पेड़ के नीचे से हट जाओ वरना तेज़ आंधी के सबब यह पेड़ गिर सकता है। उसने राहगीर की बात अनसुनी कर दी और कहा हम अल्लाह वाले हैं और अल्लाह हमारे साथ है। फिर दूसरा राहगीर उधर से गुज़रा उसने भी उस शख़्स को पेड़ के नीचे से हटने की सलाह दी। उसे भी वही जवाब मिला कि अल्लाह हमारे साथ है। फिर तीसरे राहगीर के मना करने पर भी उस शख़्स ने फिर वही जवाब दिया। कुछ पल बाद वह दरख़्त गिर पड़ा और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला वह शख़्स अल्लाह को प्यारा हो गया। जब लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाले शख़्स को अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? रूमी लिखते हैं कि चूँकि अल्लाह के हुक्म से ही वह तीन राहगीर उस शख़्स को समझाने के लिए भेजे गए थे कि तू पेड़ के नीचे से हट जा। मगर अल्लाह पर भरोसा नहीं बल्कि उसकी ज़िद उसकी मौत का सबब बन बैठी।

इसलिए देशवासियों,आपका विश्वास आपका अक़ीदा आपकी मान्यताएं सब आपको मुबारक हो। आपको उनको ज़रूर मानें। परन्तु आज जब पूरी दुनिया आपसे सहयोग की अपेक्षा कर रही है। भीड़ भाड़ इकठ्ठा न करने, व एक दूसरे

से उचित फ़ासला बनाकर रखने की सलाह दे रही है।

स्वयं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की अपील कर रही हो उसके बावजूद आप डॉक्टर्स की सलाह मानने के बजाए अपनी वाली ही करने की ठानें। अन्धविश्वास में ही इस महामारी का हल तलाश करने लगें तो आप भी पेड़ के नीचे खड़े रहने की ज़िद करने वाले इंसान की ही तरह हैं। और फिर आपका भी अल्लाह ही मालिक है। ■

मानवता के दुश्मन हैं 'लॉक डाउन' की धज्जियाँ उड़ाने वाले

✍ निर्मल रानी

इतिहास में पहली बार कोरोना वायरस के चलते विश्व के सामने सबसे बड़ा संकट छाया हुआ है। जब तक इस लाईलाज महामारी का कोई सटीक ईलाज नहीं निकल आता तब तक स्वयं को इस महामारी से बचाए रखना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच समझा जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना प्रभावित दुनिया के अधिकांश देश इस समय तालाबन्दी या सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रखने पर अधिक ज़ोर दे रहे हैं।

इतिहास में पहली बार भारत सहित विश्व के कई देशों में, अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख देने वाले लॉकडाउन जैसे सख़्त क़दम इसी मक़सद के तहत उठाये गये हैं। सवाल यह है कि जब देश की सरकारें देश की अर्थव्यवस्था से अधिक महत्व देशवासियों के जीवन की रक्षा को दे रही हों, ऐसे में यदि कुछ लोग या कोई संगठन अथवा कोई सांप्रदायिक समूह सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन की नीति की धज्जियाँ उड़ाए और इन्हें धत्ता बताते हुए धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करे ,जलसा ,जुलूस निकाले अथवा सड़कों पर सामूहिक रूप से उतर कर नाच गाना, हुल्लड़ बाज़ी करे तो समाज के ऐसे लोग निश्चित रूप से माफ़ी के क़तई हक़दार नहीं हैं।

परन्तु दुर्भाग्यवश सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर कुछ लोग जो स्वयं को तथाकथित धार्मिक,राष्ट्रवादी यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्त्ता व मोदी समर्थक होने का ढोंग करते हैं, वे भी लॉक डाउन की धज्जियाँ उड़ाने में व्यस्त हैं। पिछले दिनों दिल्ली स्थित निज़ामुद्दीन जैसी अत्यंत भीड़-भाड़ वाली जगह से बड़ी संख्या में जमाअत के सदस्य पाए गए। ख़बरों के अनुसार इनमें दर्जनों जमाअती विदेशी नागरिक थे और इनमें से कई कोरोना पॉज़िटिव भी बताए जा रहे हैं। इनमें कई लोगों के कोरोना के कारण मरने की भी ख़बर है। देश के विभिन्न धर्मों के और भी कई धर्मस्थलों से इसी तरह की भीड़ इकट्ठी होने की ख़बरें मिलीं। ऐसे अधिकांश स्थानों से जुड़े ज़िम्मेदारों का कहना है कि चूँकि यह लोग लॉक डाउन की घोषणा से पहले से यहाँ आए हुए थे और लॉक डाउन की घोषणा के बाद अपने अपने गंतव्यों तक नहीं जा सके इसलिए यहाँ पनाह लेने के सिवा इनके पास कोई चारा भी नहीं था।

इनमें जमाअत के लोगों का कहना है कि उन्होंने लॉक डाउन की घोषणा के बाद दिल्ली के कई संबंधित अधिकारियों को पूरी स्थिति से लिखित रूप से अवगत कराते हुए मरकज़ में रह रहे लोगों की जानकारी भी दी थी तथा इन्हें यहाँ से निकालने के लिए बसों की भी मांग की थी । परन्तु दिल्ली सरकार की तरफ़ से कोई सहायता नहीं की गयी। परिणाम स्वरूप इस प्रशासनिक अनदेखी ने

महामारी को और अधिक हवा देने का काम किया। अब यह ग़लती जमाअत प्रमुख की है या दिल्ली के अधिकारियों की,निश्चित रूप से यह जांच का विषय है। परन्तु यह तो तय है कि इस लापरवाही ने मानवता को भरी क्षति पहुंचाई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच तीन बार देश की जनता को संबोधित भी किया। सर्वप्रथम उन्होंने 22 मार्च को देश में जनता-कर्फ़्यू लगाए जाने की घोषणा की तथा जनता से आह्वान किया कि उसी दिन 5 बजे सायंकाल अपने घर के दरवाज़े पर या बालकनी-खिड़कियों के सामने खड़े होकर पांच मिनट तक ताली या थाली बजा कर उन लोगों के प्रति कृतज्ञता जताएं, जो हमें कोरोना से बचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस वैश्विक महामारी का मुक़ाबला करने के लिए दो बातों की आवश्यकता है, पहला संकल्प और दूसरा संयम। परन्तु 22 मार्च को 5 बजे शाम जब प्रधानमंत्री के आवाह्न पर देश 5 मिनट ताली व थाली बजा चुका उसके बाद देश में अनेक स्थानों पर यही ताली व थाली पीटने वाले लोग जुलूसों के शक्ल में ताली, थाली, घंटी, घंटा व शंख आदि बजाते हुए सड़कों पर उतर आए। बेशक यह लोग मोदी की जयजयकार कर रहे थे, परन्तु इन्होंने प्रधानमंत्री के कहने के विपरीत अपना संयम भी खोया और जनता कर्फ़्यू का उल्लंघन भी किया और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ भी उड़ाई।

दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च रात्रि 8 बजे देश के नाम सम्भोदन करते हुए यह घोषणा की की पूरा देश रात्रि 12 बजे से लॉक डौन कर दिया जायेगा अगले 21 दिनों की लिए। लॉक डौन खुलने का तारीक 15 अप्रैल उन्होंने बताया। उसी वक्त भारत भर में कई लोग मोदी जी की राष्ट्र की नाम सन्देश वही छोड़ कर अपने पास की दुकानों में जा कर राशन, खाद्य और जरुरी सामग्री का बंदोबस्त करने चले गए । इस कारण दुकानों में हजारो की तादात में लोगो की भीड़ हो गयी। लोग यह सोच कर की अगले 21 दिन कैसे चलाएंगे, जिस सोशल डिस्टन्सिंग की बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था वह ताक में रख कर अपने चीजों की मांग करने लगें । कई जगह तो स्थिति गंभीर हो गयी थी । दवाई की दुकानों से एक बार में हैंड सैनिटाइजर और मास्क मिंटो में ख़तम हो गए।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 5 अप्रैल को देशवासियों से रात नौ बजे नौ मिनट के लिए दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ़्लैश लाइट जलाने का आग्रह किया। पीएम मोदी की इस अपील को भी देश का समर्थन मिला। परन्तु प्रधानमंत्री ने तो 9 मिनट के लिए केवल दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने का आग्रह किया था। परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर इन नौ मिनटों के दौरान और 9 मिनट के बाद जो कुछ देखने को मिला वह बेहद शर्मनाक और प्रधानमंत्री के आवाह्न की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ने वाला दृश्य था। देश के कई इलाक़ों में इस दौरान बड़े अतिशबाज़ियाँ जलाकर प्रदूषण फैलाया गया। यह किसी की समझ में नहीं आया कि आतिशबाज़ी चलाकर स्वयं को मोदी समर्थक बताने व जताने वालों ने इस महामारी का स्वागत किया या इससे होने वाली विश्वव्यापी मानवीय क्षति पर जश्न या उत्सव मनाया। ■

उत्तर प्रदेश : लाकडाउन में भी गरीबों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं ग्राम प्रधान

✍ सौरभ सिंह सोमवंशी

जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश कुमार अपने कार्यालय में बैठे हुए थे उनके पास मोबाइल के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। जिसमें पचोखर गांव का एक पीड़ित सुभाष निषाद यह कह रहा है कि हमारे गांव के प्रधान पति श्री पहाड़ू यादव ने हमारे खाते से 4900 रुपए निकाल लिए और हमें सिर्फ 400 रूपये दिया। इसमें बैंक मित्र ने भी प्रधान पति की मदद की। जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने थाना लाइन बाजार एस ओ को फोन कर प्रधान पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जेल भेजने का आदेश दिया ।

दूसरा मामला आजमगढ़ का है जहां पर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह के पास ऐसी शिकायत आई जिसमें व्हाट्सएप एवं मैसेज के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई की अजमतगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत सालेपुर व पुनापार के संबंधित ग्राम प्रधान व सहयोगियों द्वारा श्रमिकों से अंगूठा लगवा कर 95त्न धनराशि प्रतिशत धनराशि हड़पने का प्रयास और धमकी दी जा रही है। जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को टीम बनाकर जांच करने के निर्देश दिए गए जिसमें पाया गया कि ग्राम प्रधान सालेपुर के ग्राम प्रधान के पति हरी सेवक सिंह वह पुनपार के ग्राम प्रधान भीम चंद व सहयोगी सोनू सिंह द्वारा श्रमिकों के मनरेगा की धनराशि हड़पने व श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा था। जिसका संज्ञान लेकर जिलाधिकारी नगेन्द्र प्रसाद सिंह ने ग्राम पंचायत सालेपुर के ग्राम प्रधान के पति हरी सेवक सिंह एवं ग्राम प्रधान पुनापार के ग्राम प्रधान भीम चंद व उनके सहयोगी सोनू सिंह के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराई। डीएम ने पुलिस अधीक्षक से कहा की उक्त संबंधित ग्राम प्रधानों व उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी आज ही कराये। इसी के साथ जिलाधिकारी ने समस्त ग्राम प्रधानों को सख्त हिदायत दी कि श्रमिकों के साथ न्याय करें कार्य में पारदर्शिता रखें , यदि कोई ग्राम प्रधान उक्त कृत्य में शामिल होता है तो सम्बन्धित ग्राम प्रधान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

तीसरा मामला प्रतापगढ़ के मदाफरपुर के शाहपुर गांव का है जहां पर 2 महिलाएं फूला देवी और रामदुलारी ने अपने गांव के प्रधान पति के ऊपर आरोप लगाया कि उसने दोनों महिलाओं को बैंक बुलाया और कहा कि आप लोग अपना पैसा जिसको सरकार ने भेजा है आकर ले लीजिए वहां पर दोनों से 2500 और 3000 के विद्ड्राल फार्म पर हस्ताक्षर करवाया गया परंतु दोनों को ?100 देकर वापस भेज दिया गया बाद में इन दोनों महिलाओं ने कोहंडौर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की इंस्पेक्टर कबीर दास के बताया कि दोनों महिलाओं ने शाम तक शिकायत वापस ले ली परंतु एस ओ प्रवीण कुशवाहा के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है।

यह स्थिति केवल उत्तर प्रदेश के एक दो या तीन जिले की नहीं है यह स्थिति पूरे प्रदेश की है जहां पर ग्राम प्रधानों के द्वारा मनरेगा मजदूरों के पास बुक, एटीएम यहां तक कि हस्ताक्षर किए हुए ब्लैंक चेक भी रख लिए जाते हैं और इसी की शर्त पर उनको काम दिया जाता है यहां तक की काम करने वाले मजदूरों के खून पसीने की कमाई जो सरकार के द्वारा निर्धारित कर दी गई है उसने भी ग्राम प्रधान इस तरह से कमीशन लेता है जैसे वो अपने पास से काम करवा रहा है। इसके अलावा सरकारें जितना आसानी से पैसा भेज कर यह सोचती हैं कि मजदूर के पास पैसा पहुंच गया यह बहुत कठिन है और अव्यवहारिक भी है क्योंकि यह पैसा खून पसीने को लगाकर मजदूरी करने वाला मजदूर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि प्रधान की इच्छा के अनुसार ही निकलता है।ऐसा बहुत सारे जिलों में देखा गया है और जौनपुर इसकी बानगी मात्र है। सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में 90फीसदी प्रधानों का दिन बैंक शाखाओं के सामने स्थित चाय की दुकानों पर बीतता है।जब इस सिलसिले में मजदूरों से बात की जाती है तो मजदूरों का जवाब होता है कि यदि हम सभी ग्राम प्रधान के इस कार्य का विरोध करेंगे तो ग्राम प्रधान हमारा नाम काट देगा और हम काम के लिए तरस जाएंगे अतः हमें ग्राम प्रधान की मनमानियों को सहन करना पड़ता है इसके अलावा बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो ग्राम प्रधान के द्वारा होते हैं इसके अलावा गरीब मजदूर अपने ग्राम प्रधान को कतई नाराज नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको उस ग्राम प्रधान से कई सारे लाभ लेने होते हैं। प्रतापगढ़ के मदाफरपुर में ऐसा ही हुआ होगा। जहां पर दबाव में आकर महिलाओं ने शिकायत वापस ले ली होगी।ग्राम प्रधानों का भ्रष्टाचार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बहुत सारे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत है ग्राम से बाहर प्रदेश में रहते हैं उनके नाम का जॉब कार्ड बनाकर उनको मजदूर दिखाकर उनके खाते में आए हुए पैसे में से एक मोटी राशि कमीशन के रूप में लेकर भी ग्राम प्रधान सरकारी धन को चूना लगा रहे हैं । पूरे देश में कोरोनावायरस जैसी महामारी के चलते उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में ?1000 के हिसाब से कुल 611 करोड रुपए सिर्फ इसलिए भेज दिए ताकि इन मजदूरों को लाक डाउन के दौरान कोई दिक्कत ना हो लेकिन जौनपुर में हुए घटनाक्रम इस बात की तस्दीक करते हैं कि सरकार ने हिंदुस्तान के आम गरीब दबे कुचले और वंचित तबके को ध्यान में रखकर जिस तरह की योजनाओं को बनाया है उसका पालन किस तरह से हो रहा है और जमीन पर उसकी सच्ची हकीकत क्या है? ■

सज्जन शक्तियों को प्रतिष्ठित करने का समय

✍ देवदत्त दुबे

समाज में दो धाराएं देखी जाती है, एक वे लोग हैं जो अवैध और अनैतिक तरीके से पद और पैसा अर्जित करते हैं और समाज में प्रतिष्ठा बनाते हैं वहीं दूसरी ओर वे लोग हैं जो दिन रात प्रदूषण के खिलाफ नशे के खिलाफ समाज में बढ़ रही बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करता हुआ गुमनामी के अंधेरे में जीता है। इसके लिए वह समाज भी कम दोषी नहीं है जो पद और पैसा वाले हो प्रतिष्ठा देते हैं लेकिन समाज और प्रकृति से प्रेम करने वाले को इग्नोर करते हैं। कोरोना महामारी ने दोनों ही धाराओं का महत्त्व दिखा दिया है। अब जरूरत है, कि हम समाज में उन सज्जन शक्तियों को प्रतिष्ठित करें जो हमारे सुखमय जीवन के लिए प्रयास करते रहते हैं। ना कि उनको जो अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए मानव जीवन को संकट में डाल रहे हैं।

सोचो आज आपको कौन सही लग रहा है, वे लोग जो प्रकृति का दोहन करके कुबेर हुए हैं, पहले जंगल की अदा धुंध कटाई की फिर नदियों को रेत निकाल कर छलनी कर दिया इतना प्रदूषित कर दिया की गंगा और नर्मदा नदी भी इनसे बच नहीं पाए पैसा कमाने के लिए के लोग किस तरह से नशे को घर-घर पहुंचाते है। यहां तक पहुंच गए हैं कि जिन चीजों में हमने कभी कल्पना नहीं की थी वह भी अब शुद्ध नहीं रहे तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ, सब्जियां, यहां तक कि दूध भी मिलावटी आने लगा और इन सब प्रदूषक चीजों को खाने से अनेकों बीमारियों ने मानव जीवन को खतरे में डाल दिया है। कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, ने जिस तरह से पैर पसारे हैं, उससे किसी को भी अब अपनी जिंदगी सुरक्षित नहीं लगती, बल्कि जिस तरह से जीव जंतुओं पशु पक्षियों को मारा गया है अब उसी तरह से दुनिया के कई देशों में मनुष्य मर रहा है।

पूरी दुनिया की ऐसी भयावह तस्वीर देखने के बाद, हमें जरूर अब वे लोग ठीक नहीं लगेंगे जो मानव जीवन को संकट में डाल कर पद और पैसा अर्जित करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे अनेकों लोग हैं, जिन्होंने अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर पूरा जीवन मानव जीवन को सुखी बनाने प्रकृति को बचाने, जल स्रोतों का संरक्षण करना में लगा दिया लेकिन समाज ने उन्हें वह प्रतिष्ठा नहीं दी जिसके वे हकदार थे या फिर उनके पीछे भी नहीं चले अन्यथा इतनी भयावह स्थिति नहीं बन पाती कौराना वायरस महामारी से भी ज्यादा नुकसान मानव समाज का हो चुका है। आज कुछ भी शुद्ध खाने को नहीं मिल रहा है यहां तक कि प्रकृति ने हमें जो निशुल्क दिए थे हवा और पानी वह भी छीन लिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बाद मानव जीवन मैं और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यदि हमने समय रहते समाज के असली हीरो उन सज्जन शक्तियों को प्रतिष्ठित नहीं किया जो प्रकृति और मानव जीवन को बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं।

यह समय ऐसे ही संकल्पों से संकल्पित होने का है। जिसमें सबसे पहले हम अपनी जरूरतें कम करें प्रकृति का दोहन ना करें जल स्रोतों का संरक्षण करें, जैविक खेती शुरू करें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अब आगे आना होगा और ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर लेनी चाहिए जो अवैध और अनैतिक कामों के बल पर शक्तिशाली हो रहे हैं। जबकि प्रकृति और समाज के संरक्षण के लिए कार्य करने वाले लोगों को शक्तिशाली होना चाहिए था।

कहीं देर ना हो जाए!

डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग

घरों में सिमटा, नियम संयम से जीता मानव क्या अब ये समझने के किए तैयार हो गया है कि, करोना संकट मानव जाति के लिए करुणा के सबक लेकर आया है ?

भयाक्रांत मानव, डर से ही सही, लेकिन बेजुबानो, धरा और पर्यावरण के लिए सहिष्णु हो चला है और यह तो अब आपदा से उबर जाने के बाद, आनेवाला कालखंड ही बताएगा कि मानव ने वाकई सबक सीखा और स्थायी दयालुत्व को प्राप्त हुआ अथवा नहीं क्योंकि इससे भी भयानक आपदाएं पहले आ चुकी हैं और तब कम संसाधनों के बावजूद, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते मानव जाति भयंकर जानमाल पशुधन के नुक्सान के बावजूद हर बार उठ खड़ी

हुई थी। लेकिन फिर भी उसने सबक नहीं सीखे और बेजुबानों, मजबूर प्राणियों, पर्यावरण, पेयजल स्त्रोतों का ना तो ध्यान रखा और ना ही उनके संरक्षण का कोई सामजिक सशक्त प्रयास ही किया।

करोना उर्फ़ कोविड19 उर्फ़ सार्स करोना श्रृंखला का सातवां वायरस, चीन के कुत्सित इरादों का प्रतिफल और अभिशाप है। दुनिया के लिए, सैकड़ों अन्य वाणिज्यिक हथियार, युद्ध हथियार और केमिकल हथियारों की तरह यह भी एक हथियार ही है और सम्पूर्ण जगत को, प्राणियों को, इसका तांडव झेलना पड़ रहा है।

यह एक प्रकृति या ईश्वरीय कहर है या मानव रचित विषाक्त हथियार। यह बहस अब बेमानी हो चली है लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि 1347-1352 में जब चूहों से जानलेवा प्लेग फैला था तब शुरुआत और सबसे गंभीर जानमाल के नुकसान इटली ने ही झेले थे, अठ्ठारहवीं सदी में यलो फीवर की महामारी और उन्नीसवीं सदी में कोलेरा भी इसी भूभाग से फैला, 1918 में खूनी इन्फ्लुएंजा ने तो इस क्षेत्र को बेदम कर दिया था और आज भी करोना का मारा इटली ही मौत के मुहाने पर खड़ा नेस्तनाबूद हो चुका है। जो यह बार-बार सत्यापित करता है कि साफ़ सफाई, शुद्ध पेयजल, नियम और संयम, पौष्टिक शुद्ध भोजन सोशियल डिस्टेंसिंग के ढेरों मायने हैं, धरा और पर्यावरण के संरक्षण के साथ।

लेकिन क्या सब कुछ ख़तम होने की कगार पर है ?

दुनिया को भरमाने और राज करने, खुद को अजर अमर समझने वाले बड़े बड़े सूरमा, राज्य और राष्ट्र एक छोटे से, ना दिखाई देने वाले वायरस के हाथों बुरी तरह मात खाये हुए हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे ना घबरा, चंद ढीठ मानव इस बीमारी में भी बाजार देख रहे हैं और अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए करुणा की जगह करोना को तवज्जो दे रहे हैं। गोया कि सब कुछ अपने साथ ले जाने वाले हैं ।

भारत जैसे विशाल भूभाग और विशालतम जनसंख्या वाले सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश में तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है क्योंकि वोटबेंकिय राजनीति के चलते ना तो क्वालिटी जनसँख्या पर ध्यान दिया जा रहा है और ना ही बेजुबानों, पर्यावरण, पेयजल स्त्रोतों और वृक्षारोपण पर। सब कुछ मानो भीड़तंत्र और धनबल के हाथो बिका हुआ, सक्षम लूटने को बेकरार है और सरकारें कर्मठ देशभक्तों को चूस, मुफ्तखोरों का पेट भरने को लालायित।

पर कुदरत भारत के गरीब, ईमानदार मेहनकश लोगों पर मेहरबान भी दिखती है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों विश्व के धनाढ्य, विकसित, अतिशिक्षित देशो में इतनी मौतें हो रही होती और भारत जैसे गरीब देश में इतनी कम जबकि यहाँ पर केजरीवाल जैसे अराजक और मौलानाओं जैसे कूपमंडूक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ आ रहे हैं ?

इनके कुत्सित प्रयासों के बावजूद भारत ना सिर्फ अपने दम पर पूरी ताकत से खड़ा है बल्कि अल्प संसाधनो के बावजूद इस अदृश्य महादानव से लड़ भी रहा है। और इसमें उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी संयम, नीति और नियम से रहने की आदत और सीमित संसाधनों के बावजूद लड़ने, सर्वाइव करने की दृढ़ इच्छाशक्ति। साथ ही ईश्वरप्रदत्त उसकी इम्युनिटी और मददगार द्वत्रह्ल जो उसके शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत दे रहे हैं, अधिकाँश को बचपन में टीबी का टीका भी लगा हुआ है, वो भी बचाव कर रहा है इस कीटाणु से लड़ने में लेकिन देश और देश के पालनहार उस आगामी महामारी को समझ नहीं पा रहे हैं जो आने वाले समय में इस बीमारी से संक्रमित लोगों के 'केरियर स्टेज' बने रहने से होगी क्योंकि इन मरीजों से ना सिर्फ वातावरण दूषित होता रहेगा बल्कि इनके मलनिकास के जरिये वायरस पेयजल स्त्रोतों को भी दूषित करता रहेगा।

यहाँ एक बार फिर यह बताना बेहद जरुरी है कि, इस वायरस से सर्दी, जुखाम, बुखार, शरीर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ के अलावा सरदर्द और अंत में निमोनिया से मृत्यु होती है यह तो सबको पता ही हैं लेकिन यह वायरस फीको ओरल रुट (अर्थात भोजन नलिका के जरिये मलनिकास द्वारा) के जरिये भी आपके पेय जल को दूषित कर फ़ैल सकता है और सांस के लक्षणों से पहले मरीज को उलटी दस्त, पेट में दर्द मरोड़, पीलिया हो सकता है, यहाँ तक कि लिवर भी खराब हो सकता है।

अर्थात मानव को खांसी, छींक के जरिये ड्रॉपलेट के संपर्क में आने से बचने के सारे प्रयास, जैसे मास्क पहनना, भीड़ में ना जाना, बार-बार हाथ धोना, कंम्यूनिटी फैलाव रोकने के लिए संभावित लोगों को खुद को आइसोलेट तो करना ही चाहिए। लेकिन अब यह भी आवश्यक हो गया है कि जनता पूरी ताकत से अपने पेय जल स्त्रोतों को भी सुरक्षित करे, करवाए और सरकारें, अदालतें जलसंक्रमण को गंभीर अपराध घोषित करें।

कोई सुन रहा है क्या ? आदरणीय प्रधानमंत्रीजी, सीजेआई साहब और हमारे मामाजी उर्फ़ शिवराजजी, महाराज जी। इसके पहले की कहीं देर हो जाए, संज्ञान ले लीजिये। ■

खामोशी से भी नेक काम होते हैं मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए

देवदत्त दुबे

दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन कई बार उन्हें अवसर नहीं मिलता। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा नेक काम घर में रहने का है और दुर्भाग्य से ही सही यह अवसर उन सब को प्राप्त है जो बाहर जाकर कोई मदद नहीं कर सकते केवल घर में रहकर अपनी और पूरी मानव जाति की मदद कर सकते हैं।

दरअसल जिस तरह से दुनिया के संपन्न और शक्तिशाली देश कोरोना महामारी के चलते लड़खड़ा गए हैं, उससे भारत जैसे देश में बीमारी से बचाव ही एकमात्र उपाय रह गया है। अन्यथा की स्थिति में परिस्थिति कितनी भयावह हो सकती है कुछ कहा नहीं जा सकता है।

पूरे देश में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मध्यप्रदेश में मरीजों की संख्या ढाई सौ से ज्यादा हो गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से लेकर क्लर्क तक कोराना की चपेट में आ चुके हैं। यह विभागीय ही है जो कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिन-रात जटा है और इस विभाग के 10 लोग प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैदान में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी भी संक्रमित होने लगे हैं। अभी तक जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर जैसे महानगरों में कोरोना सीमित था। लेकिन धीरे-धीरे प्रदेश के अन्य अन्य जिलों मुरैना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, खरगोन, बड़वानी, के साथ-साथ सिरोंज जैसे कस्बे में भी पहुंच गया है।

शासन-प्रशासन कोरोना की जांच करने के लिए संसाधन तैयार कर रहा है। अस्थाई अस्पताल तैयार कर रहा है क्योंकि यदि लोगों ने लॉक डाउन का उल्लंघन किया और संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी, तो फिर वर्तमान अस्पताल कम पड़ जाएंगे।

कुल मिलाकर कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय घरों में रहने में ही है और इससे बड़ा नेक काम और कुछ नहीं हो सकता इस समय। पूरे देश से जो खबरें आ रही हैं जिस तरह से नर्स और डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों को ठीक कर रहे हैं और घर भी नहीं जा रहे हैं, पुलिस वाले भी दिन रात की ड्यूटी करते हुए घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहां तक कि मध्यप्रदेश के जेलों में बंद कैदी मास्क तैयार करने में जुट गए हैं। इससे भी वे लोग सबक ले सकते हैं जो बेवजह घर से बाहर निकल कर मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।

जब स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे शक्तिशाली देश भी लॉक डाउन को ही कोरोना महामारी से निपटने का एकमात्र विकल्प बता रहे हैं, तब भारत जैसे देश में बेहद जरूरी हो गया है कि केवल और केवल लॉक डाउन का पालन करें, और इस समय का सबसे बड़ा नेक काम करने का उदाहरण पेश करें।

शक्ति पर्व पर भारत ने फिर दिखाई शक्ति

जो विदेशी लोग कभी भारत पर बात-बात पर तंज कसते थे यहां की व्यवस्थाओं पर, यहां के लोगों पर, यहां की आस्था पर, यहां के विश्वास पर, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर, यहां की यातायात व्यवस्थाओं पर, यहां की जीवन शैली पर, वही दुनिया अब भारत की कोरोना महामारी के खिलाफ जंग देखकर दंग है। वो जो तंज कसते थे कि भारत में जीवन भगवान भरोसे है अब वे मान गए कि वाकई में भारत में कोई अदृश्य शक्ति है जो इतनी अव्यवस्थाओं के बाद भी भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ रहा है।

शक्ति पर्व नव दुर्गा के अंतिम दिवस रामनवमी के रूप में एक बार फिर ऐसा लगा, जैसे इतिहास दोहराया गया हो। अब भगवान राम ने वानरों के सहयोग से तब की महामारी शक्तिशाली रावण को परास्त किया था। आज भारत देश भी लचर स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के बावजूद, जनसंख्या के सबसे अधिक घनत्व के बावजूद, आज के राक्षस कोरोना महामारी जंग लड़ रहा है। जबकि इस महामारी से लड़ने के लिए दुनिया के शक्तिशाली देश लड़खड़ा गए, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में सरकारों के हाथ कांपने लगे हैं। वही अमेरिका जैसा देश आशंका व्यक्त करने लगा है, यदि हालात बिगड़े तो प्राण शती होने की संख्या 2000000 से ऊपर जा सकती है।

भारत देश त्याग, तपस्या, का देश माना जाता है और कुछ लोगों को छोड़ दें तो इस कठिन दौर में अधिकांश भारतीयों ने त्याग तपस्या का परिचय दिया है। अधिकांश लोग जहां घोसला में कैद होकर हौसला दिखा रहे हैं, वही वे लोग धरती पर आधुनिक आवतार ही माने जा रहे हैं, जो अपनी जान हथेली पर रखकर जान की बाजी खेलकर लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, जिन पर देशवासियों को गर्व है वही दुनिया नतमस्तक है लेकिन हर दौर में आसुरी प्रवृत्तियां विघ्न डालने का काम करती आई हैं। ऐसी ही कुछ प्रवृत्तियों ने इंदौर में ऐसा शर्मनाक कृत्य किया है, जिसके लिए शायद भगवान भी माफ ना करें क्योंकि कुछ लोगों ने उन डॉक्टरों पर जानलेवा हमला किया है, जो उन्हीं लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर उनके घर गए थे।

कुल मिलाकर भारत में शक्ति पर्व पर दुनिया को अपनी शक्ति से परिचय करा दिया है कि वसुदेव कुटुंब की भावना में जीने वाला भारत देश अंततः वैसे ही विजय को प्राप्त होगा जैसे किसी भी फिल्म के अंत में खलनायक हारता है और हीरो जीतता है। वे लोग भी इस महामारी के संकट से सबक ले सकते हैं, जिन्होंने जीतने के लिए छल कपट पाखंड का सहारा लिया, जो अपनी जीत के लिए दूसरों को मार देना चाहते हैं। इन सब का अंत बुरा होता है। दुनिया में भारत ही एक देश है, जिसने कभी भी पहले से किसी भी देश पर ना तो आक्रमण किया है और ना ही ऐसा कोई काम किया है, जिससे दुनिया की मानवता को खतरा पैदा हो सके वरन दुनिया को सही रास्ता दिखाने का काम समय समय पर करता रहा है और यही अंदर का सत्व तत्व आज भारत को शक्ति दे रहा है। 9 दिन में शक्ति अर्जित कर चुका भारत देश को भगवान राम की मर्यादा भी संबल प्रदान कर रही है और अधिकांश भारतीय मर्यादा का पालन कर रहे हैं, जो लोग इस समय मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्योंकि यह समय धैर्य और संयम का है, जब दुनिया की बहादुरी नहीं चल पा रही तो हम घरों से बाहर निकलकर कौन सी बहादुरी दिखाना चाहते हैं, अभी तो जिस किसी को भी बहादुरी दिखाना है वह दिखा सकता है घर के अंदर रहकर किसी भी प्रकार की नशे को विदा करके अपने आस पड़ोस किसी जरूरतमंद की मदद करके और आगे के लिए शुभ संकल्पों को तय करके।

सनातन का अस्तित्व और भारत

✍ **एस के सिंह**

अस्सी के दशक में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के प्रति सिख समुदाय की जो नफरत थी , उस से कहीं सौ गुना नफरत इस समय मुस्लिम समाज की नफरत नरेंद्र मोदी , भाजपा और सनातनी शक्तियों के प्रति दिख रही है। यह नफरत पाकिस्तान , बांग्लादेश और चीन की सरहद तक जाती है। सिर्फ दिल्ली , हरियाणा , पंजाब तक नहीं , इस तथ्य को अगर कोई सदाशयता में भी अनदेखा कर रहा है तो निश्चित रूप से वह अंधा है। समस्या यह है कि सेक्यूलर हिप्पोक्रेटों ने इस नफरत को वैचारिक ज़मीन दी है। उबाल और नफरत तो 2014 ही से थी। स्मरण करें फारुख अब्दुल्ला जैसों के बयान जो मोदी को वोट देने वालों को समंदर में डुबो रहे थे। तत्कालीन गतिविधियों को याद कीजिए। यह भी याद कीजिए जब कुछ लोग मोदी के जीतने पर देश छोड़ने की धमकी दे रहे थे। अमर्त्य सेन जैसे लोगों की आर्थिक नौटंकी याद कीजिए। खैर , वह कांग्रेसी पैसे पर नाच रहे थे और अपने नोबल पुरस्कार को डुबो रहे थे। गाय वाय फिर शुरू हुआ। अवार्ड वापसी , जे एन यू में जहर की फसल वगैरह याद कर लीजिए। गोहत्यारों के बचाव में माब लॉन्चिंग का नैरेटिव आदि-इत्यादि। नोटबंदी , जीएसटी के कुचक्र के बहाने नफरत और नागफनी के तमाम पड़ाव पार कर जब 2019 का चुनाव भी जीत लिया मोदी ने तब ही इस गृहयुद्ध की बुनियाद रख दी गई। इस्लाम फर्स्ट , नेशन सेकंड की अवधारणा में जीने वाले , वंदे मातरम और भारत माता की जय का मजाक उड़ाने और तौहीन करने वाले लोग अब संविधान बचाने का राग ले कर तिरंगे की आड़ लेकर उपस्थित हो गए। तीन तलाक , कश्मीर में 370 के खात्मे ने उन की बुनियाद में उर्वरक का काम किया। लेकिन कोई राजनीतिक कंधा नहीं मिल रहा था। अब आया सीएए। कांग्रेस ने राजनैतिक अस्तित्व के लाभ के लिए कंधा थमा दिया। कह दिया , सड़क पर उतरो। कांग्रेस के टट्टू कम्युनिस्टों ने शाहीन बाग़ सजा दिया। सोए जे एन यू को जगा दिया। जामिया मिलिया को जला दिया। आज तक जामिया हिंसा में एक नहीं मारा। लेकिन अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लगायत जाधवपुर यूनिवर्सिटी तक जामिया के शहीदों की शहादत तापने के लिए एकजुट हो गए।

दिसंबर में हुए देशव्यापी उपद्रव में मोदी सरकार ठीक आकलन करने से चूक गई। जनसंख्या नियंत्रण क़ानून , कॉमन सिविल कोड , एनआरसी आदि की तैयारी में लगी रही। कि दिल्ली तीन दिन के दंगे में झुलस गई। तब मोदी सरकार की नींद

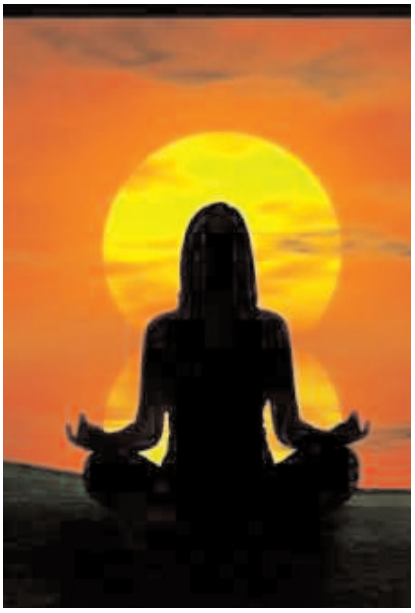

टूटी। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत ! देश गृह युद्ध की नाव पर बैठ चुका था। वारिस पठान कहने लगा था 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हैं। क्या कार्रवाई हुई वारिस पठान पर। उतर पूर्व को देश से काटने के आह्वान के साथ शरजील इमाम खड़ा हो गया। अभी तो यह शेरनियां हैं। जैसी बातें होने लगीं। तो क्या यह सब लोग जनगणमन गा रहे थे ? शहर दर शहर शाहीन बाग़ खुल गए। मोदी सरकार ने क्या कर लिया इन का। नतीजा सामने है। गृह युद्ध के इन सिपहसालारों को कोई कोरोना , फोरोना का भय नहीं रह गया है। जो लोग मुसलामानों के अनपढ़ , जाहिल होने के तर्क दे रहे हैं , वह नादान लोग हैं। राहत इंदौरी तो चलिए पुराने कटटर हैं। लीगी हैं। लिखते ही रहे हैं किसी के बाप का हिन्दोस्तान थोड़े ही है। लिखते ही रहे हैं कि कब्रों की ज़मीने दे कर मत बहलाइए / राजधानी दी थी राजधानी चाहिए। मुनव्वर राना भी एक मां के बहाने लोकप्रिय हो कर इस्लाम का ही तराना गाते रहे हैं। लेकिन जावेद अख्तर ? जावेद अख्तर तो राज्य सभा में भारत माता की जय बोलने वालों में से थे। उन को अब क्या हो गया ? दस बरस तक उप राष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी को क्या हुआ ? आमिर खान , शाहरुख़ खान , नसीरुद्दीन शाह सभी का डर जोड़ लीजिए। तमाम और डर जोड़ लीजिए। तो क्या 370 की आड़ में जो हिंसा हो रही थी , देशद्रोही कारनामे हो रहे थे , वह डरे हुए मुसलमानों का कारनामा था ? और अब जो मुसलसल छ महीने से हो रहा है , वह डरे हुए लोग कर रहे हैं ? कोरोना से भी नहीं डरने वाले लोग मोदी सरकार से डरे हुए हैं ? किस की आंख में धूल झोंक रहे हैं भला आप। आप की आंख पर पट्टी बंधी हुई है तो बांधे रहिए।

पर आप मानिए न मानिए मुस्लिम समाज के अराजक तत्वों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वह कोरोना को गले लगा कर पुलिस पर सरेआम गोली तान सकते हैं। डाक्टरों पर थूक सकते हैं। जिन नर्सों का दुनिया भर में सम्मान हो , जिन्हें सिस्टर कहा जाता हो , उन के सामने नंगे नाच सकते हैं। अश्लील हरकतें कर सकते हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी की प्रैक्टिस तो इन्हें मक्का और कश्मीर से ही है। लेकिन कोरोना की इस विपत्ति में निजामुद्दीन मरकज से निकल कर पूरे देश में फ़ैल कर तबलीग जमात के लोगों द्वारा कोरोना को बढ़ाने का यह हिंसक हौसला कुछ तो कहता ही है। फिर टिक टाक पर जो कोरोना फ़ैलाने के लिए परोसे गए बेशुमार वीडियो हैं , उन का क्या करें। उस में भी बच्चों का बेधड़क इस्तेमाल साफ़ बताता है कि मोदी सरकार का इकबाल और धमक मुस्लिम समाज में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब भी अगर मोदी सरकार नहीं चेती , इन अराजक और हिंसक लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती तो तय मानिए भारत अब गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। किसी एक गांव , किसी एक शहर की बात नहीं है। देश भर की मस्जिदों से निरंतर लोग निकाले जा रहे हैं। विदेशी लोग भी। मुस्लिम समाज द्वारा सीएए के बहाने लॉक डाऊन का देशव्यापी विरोध और कोरोना फ़ैलाने की सनक से भी सरकार की आंख नहीं खुलती तो फिर आने वाला समय बहुत संकट में डालने वाला है देश को। कम से कम गृह युद्ध को ऐसी स्थिति में बिना कड़ी कार्रवाई के आप नहीं टाल सकते। छिटपुट रासुका लगाने से यह संकट टलता नहीं दीखता।

विचार करे!
मंथन और चिंतन करें।
राष्ट्र सर्वोपरि।

कोरोना पैकेज : डिजिटल सिस्टम और अफसरी फांस

✍ डॉ. अजय खेमरिया

कोरोना संकट से निबटने के लिए देशवासी मुक्त हस्त से दान कर रहे हैं। यह दान पीएम केयर फंड और राज्य के मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया जा रहा है। हृदय को प्रफुल्लित करने वाले दृश्य भी इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। बच्चे अपनी गुल्लक तोड़कर इस फंड के लिए धन दे रहे हैं। कोई अपने प्रिय परिजनों की तेरहवीं के धन को दान कर रहा है। वर पक्ष के लोग विवाह में दिए जाने वाले दहेज़ को पीएम केयर में देने की सलाह वधु पक्ष को दे रहे हैं। कश्मीर में एक महिला ने हज जाने के लिए रखी 5 लाख की राशि संघ के सेवाभावी स्वयंसेवकों को दान कर दी। इनके अलावा लाखों लोग भोजन, राशन, दवा, परिवहन के सेवा प्रकल्प में स्वप्रेरित भाव से संलग्न हैं।

सुकूनभरी इन तस्वीरों का दूसरा पक्ष सरकारी सिस्टम की जड़ता और दुरूह कार्यप्रणाली का भी खड़ा हो रहा है। केंद्र सरकार ने 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। किसान, मजदूर, महिला, दिव्यांग वर्ग के लिए जो प्रावधान किए हैं, उन्हें अफसरशाही और बाबूशाही की अजगर फांस से बचाना प्रशासन तन्त्र का सबसे चमत्कारिक घटनाक्रम होगा। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की है कि राज्य में बगैर राशन कार्ड वाले जरूरतमंदों को भी सरकारी दुकानों से मुफ्त राशन दिया जाएगा। इस बीच प्रदेश में करीब दो लाख परिवार ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा गारन्टी के दायरे से बाहर हैं। इन परिवारों के पास राशन कार्ड तो है लेकिन इनके नाम नई बायोमेट्रिक मशीनों में दर्ज नहीं हैं।इसलिए इन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है।

लॉकडाउन के बीच हर कलेक्टर दफ्तर में ऐसे लोग फरियाद लेकर खड़े हैं। सरकारी मुलाजिम नियमों का हवाला देकर चुप हैं। किसान कल्याण निधि के सरकारी पोर्टल पर 96073451 किसान पंजीकृत हैं लेकिन 11 फरवरी को केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिए जवाब में बताया कि इनमें से 84472629 किसान इस योजना में लाभान्वित हो रहे हैं। शेष 1 करोड़ 16 लाख से अधिक किसान तकनीकी कारणों से योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा बैंक खाते, आधार नम्बर दुरस्त न होने के कारण है। इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना पैकेज में भी 8.6 करोड़ किसानों को ही इस दायरे में लिया है। जाहिर है ये 1 करोड़ 16 लाख किसान परिवार 2 हजार की मदद से भी वंचित रहेंगे।

सरकार ने श्रमिकों के खातों में एक हजार रुपए डालने की निर्णय लिया है। लेकिन मप्र में ही केवल 8.6 लाख मजदूर इसके दायरे में हैं। शेष इसलिए वंचित हो गए क्योंकि सरकार ने जिस श्रम शक्ति एप के जरिये इनका पंजीयन किया था, उसमें तकनीकी कारणों से करीब एक करोड़ वास्तविक मजदूर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। केंद्र सरकार के सुगम्य भारत योजना में दिव्यांगजनों के लिए यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनाने का काम पिछले दो वर्षों से चल रहा है, इस एप्प बेस्ड डेटा में अभी आधे ही दिव्यांग रजिस्टर हो सके हैं। ऐसे में सभी लोगों तक केंद्रीय मदद कैसे सुनिश्चित होगी? असल में भारत

की प्रशासनिक मशीनरी यथास्थितिवाद और जड़ता पर अकाट्य रूप से अवलंबित है। मानवीय संवेदना अफसरशाही के दिल और दिमाग में कभी सरकारी जड़ता से ऊपर स्थान नहीं ले पाती है। यही कारण है कि लोककल्याण से जुड़ी अधिकतर योजनाएं परिणामोन्मुखी नहीं हो पाती हैं।कोरोना जैसी आपदा अभूतपूर्व है लेकिन सरकारी तंत्र इस संकट को भी परम्परागत तौर-तरीकों से निबटने में लगा है। बेहतर होता मुख्यमंत्री राहत कोष को जिला स्तर पर संचालित किया जाता क्योंकि इस कोष में लोग इस भावना से दान देते हैं कि जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचे लेकिन जिस खाते में यह धनराशि जाती है उसकी व्यय प्रक्रिया इतनी दुरूह और जटिल है कि आपदा के बाद उसका कोई वास्तविक महत्व ही नहीं रह जाता है। मसलन चादर या पलँग खरीदे जाने हैं तो पहले कलेक्टर अस्पताल से मांग पत्र लेंगे फिर कलेक्टर इस आशय के पत्र शासन को भेजेंगे, शासन धनखर्ची के लिए मार्गदर्शी नियम बनाएगा। वित्त विभाग स्वीकृति देगा। जिलों को धन जारी होगा, फिर भंडार क्रय नियमों के अनुरूप टेंडर/जेम पोर्टल प्रक्रिया होगी। वेंडर सप्लाई करेगा। कलेक्टर सबन्धित विभाग को मदद के लिए नोडल निर्धारित करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को कागज, नोटशीट, ऑर्डर पर ही दौड़ना पड़ता है। बाढ़, भूकम्प या अन्य आपदा में सहायता का यही मेकेनिज्म है। हां इससे पहले सर्वे भी होता है कि कौन पात्र और कौन अपात्र है।बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री सहायता कोष जिलावार निर्धारित कर इस जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए।

जिस जिले में इस मदद के लिये राशि न मिले उसमें सरकार राशि डाले। इसी तरह पीएम फंड भी राज्यवार दानियों के हिसाब से निर्धारित किया जा सकता है, उसके व्यय की अधिकारिता को मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव के साथ सयुंक्त किया जा सकता है। ऐसा करने से आपदा के समय सरकारी मदद को समयानुकूल और त्वरित बनाया जा सकता है। अन्यथा यह सरकारी सिस्टम के मकड़जाल में फंसी ही रहेगी। जो स्थानीय दानी हैं, उन्हें भी यह सन्तोष होगा कि उनकी राशि का उनकी नजरों के सामने ही उपयोग किया जा रहा है।सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली में किस हद तक यथास्थितिवाद है इसकी नजीर एमपी एमएलए फंड के साथ समझी जा सकती है। लगभग सभी सांसद व विधायक कोरोना मदद के नाम पर लाखों करोड़ों की राशि स्थानीय अस्पतालों को मास्क, सेनिटाइजर, वेंटिलेटर और दूसरी एसेसरीज के लिए जारी कर चुके हैं लेकिन आजतक किसी कलेक्टर ने इस राशि के कार्यादेश जारी नहीं किये हैं। जबकि आबंटन पत्रों में साफ लिखा है कि राशि किस मद में व्यय की जानी है। जाहिर है सरकारी सिस्टम की दुरूह कार्य संचालन प्रक्रिया में यह त्वरित गति से संभव ही नहीं है। जब इस राशि का उपयोग होगा तब शायद इन वस्तुओं की सामयिक उपयोगिता एक चौथाई भी न रहे। वस्तुतः हमारे प्रशासन तन्त्र की कार्यविधि में जनोन्मुखी तत्व 70 साल बाद भी सुनिश्चित नहीं हो पाया है। ऐसा इसलिए कि चुनी हुई सरकारें सिर्फ अफसरशाही के दिमाग से चलती हैं और अफसरशाही का मूल चरित्र ही जड़ता, विलंब और फिजूल कागजी पत्राचार रहता है।डिजिटल इंडिया के लक्ष्य पर जिस अंधाधुंध तरीके से काम हो रहा है उसने कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी निर्मित की हैं। इनके परिक्षालन का यह सबसे अच्छा अनुभव है। सरकार को चाहिए कि इस संकट की घड़ी में डिजिटल प्लेटफार्म को पात्रता का मापदंड निर्धारित करने की परिपाटी को शिथिल कर दे क्योंकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि करोड़ों वास्तविक लोग इसके चलते लाभ से वंचित हो रहे हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

राणा सांगा : 80घाव के बावजूद अदम्य साहसी और परमवीर

राणा सांगा जिसे मानवों का खंडहर कहा जाता था।मेवाड़ योद्धाओं की भूमि है, यहाँ कई शूरवीरों ने जन्म लिया और अपने कर्तव्य का प्रवाह किया । उन्ही उत्कृष्ट मणियों में से एक थे राणा सांगा । पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह । वैसे तो मेवाड़ के हर राणा की तरह इनका पूरा जीवन भी युद्ध के इर्द-गिर्द ही बीता लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है । एक हाथ , एक आँख, और एक पैर के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इन्होंने ज़िन्दगी से हार नही मानी और कई युद्ध लड़े ।

ज़रा सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा जब वो शूरवीर अपने शरीर मे 80 घाव होने के बावजूद, एक आँख, एक हाथ और एक पैर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद जब वो लड़ने जाता था ।।

कोई योद्धा, कोई दुश्मन इन्हें मार न सका पर जब कुछ अपने ही विश्वासघात करे तो कोई क्या कर सकता है । आईये जानते है ऐसे अजयी मेवाड़ी योद्धा के बारे में, खानवा के युद्ध के बारे में एवं उनकी मृत्यु के पीछे के तथ्यों के बारे में।

परिचय –

राणा रायमल के बाद सन् 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509- 1527 तक रहा । इन्होंने दिल्ली, गुजरात, व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली राजा थे । इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊँचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की।

राणा सांगा अदम्य साहसी थे । इन्होंने सुलतान मोहम्मद शासक माण्डु को युद्ध में हराने व बन्दी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया, यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। बचपन से लगाकर मृत्यु तक इनका जीवन युद्धों में बीता। इतिहास में वर्णित है कि महाराणा संग्राम सिंह की तलवार का वजन 20 किलो था ।

सांगा के युद्धों का रोचक इतिहास –

* महाराणा सांगा का राज्य दिल्ली, गुजरात, और मालवा के मुगल सुल्तानों के राज्यो से घिरा हुआ था। दिल्ली पर सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नसीरुद्दीन खिलजी सुल्तान थे। तीनो सुल्तानों की सम्मिलित शक्ति से एक स्थान पर महाराणा ने युद्ध किया फिर भी जीत महाराणा की हुई। सुल्तान इब्राहिम लोदी से बूँदी की

सीमा पर खातोली के मैदान में वि।स। 1574 (ई।स। 1517) में युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और भाग गया। महाराणा की एक आँख तो युवाकाल में भाइयो की आपसी लड़ाई में चली गई थी और इस युद्ध में उनका बायां हाथ तलवार से कट गया तथा एक पाँव के घुटने में तीर लगने से सदा के लिये लँगड़े हो गये थे।

ज़ महाराणा ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर को लड़ाई में ईडर, अहमदनगर एवं बिसलनगर में परास्त कर अपने अपमान का बदला लिया अपने पक्ष के सामन्त रायमल राठौड़ को ईडर की गद्दी पर पुनः बिठाया।

अहमदनगर के जागीरदार निजामुल्मुल्क ईडर से भागकर अहमदनगर के किले में जाकर रहने लगा और सुल्तान के आने की प्रतीक्षा करने लगा । महाराणा ने ईडर की गद्दी पर रायमल को बिठाकर अहमद नगर को जा घेरा। मुगलों ने किले के दरवाजे बंद कर लड़ाई शुरू कर दी। इस युद्ध में महाराणा का एक नामी सरदार डूंगरसिंह चौहान(वागड़) बुरी तरह घायल हुआ और उसके कई भाई बेटे मारे गये। डूंगरसिंह के पुत्र कान्हसिंह ने बड़ी वीरता दिखाई। किले के लोहे के किवाड़ पर लगे तीक्ष्ण भालों के कारण जब हाथी किवाड़ तोड़ने में नाकाम रहा , तब वीर कान्हसिंह ने भालों के आगे खड़े होकर महावत को कहा कि हाथी को मेरे बदन पर झोंक दे। कान्हसिंह पर हाथी ने मुहरा किया जिससे उसका शरीर भालो से छिन छिन हो गया और वह उसी क्षण मर गया, परन्तु किवाड़ भी टूट गए। इससे मेवाड़ी सेना में जोश बढा और वे नंगी तलवारे लेकर किले में घुस गये और मुगल सेना को काट डाला। निजामुल्मुल्क जिसको मुबारिजुल्मुल्क का ख़िताब मिला था वह भी बहुत घायल हुआ और सुल्तान की सारी सेना तितर-बितर होकर अहमदाबाद को भाग गयी।

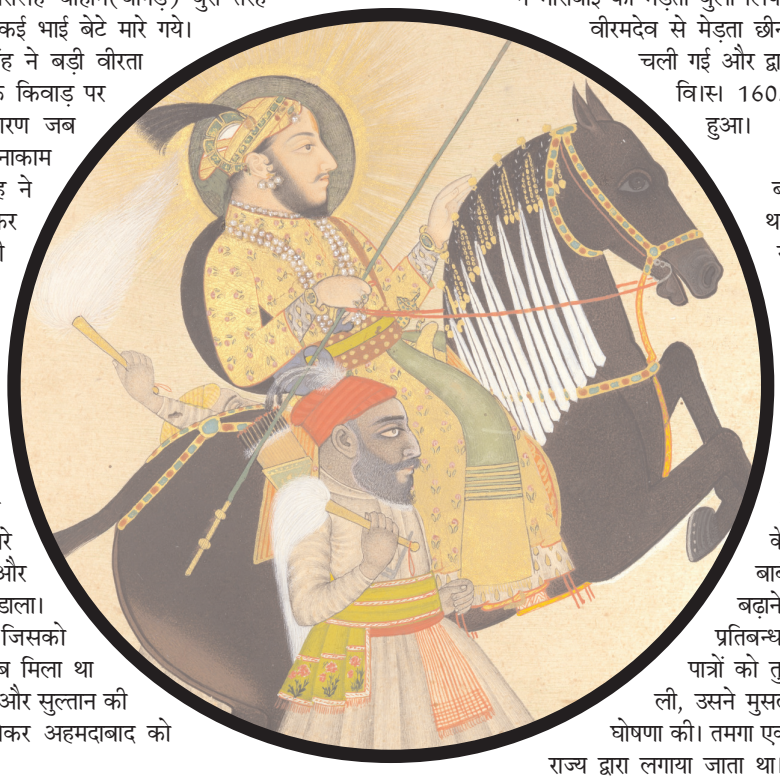

ज़ माण्डू के सुलतान महमूद के साथ वि।स। 1576 में युद्ध हुआ जिसमें 50 हजार सेना के साथ महाराणा गागरोन के राजा की सहायता के लिए पहुँचे थे। इस युद्ध में सुलतान महमूद बुरी तरह घायल हुआ। उसे उठाकर महाराणा ने अपने तम्बू पहुँचवा कर उसके घावो का इलाज करवाया। फिर उसे तीन महीने तक चितौड़ में कैद रखा और बाद में फ़ौज खर्च लेकर एक हजार राजपूत के साथ माण्डू पहुँचा दिया। सुल्तान ने भी अधीनता के चिन्हस्वरूप महाराणा को रत्नजड़ित मुकुट तथा सोने की कमरपेटी भेंट स्वरूप दिए, जो सुल्तान हुशंग के समय से राज्यचिन्ह के रूप में वहाँ के सुल्तानों के काम आया करते थे। बाबर बादशाह से सामना करने से पहले भी राणा सांगा ने 18 बार बड़ी बड़ी लड़ाईयाँ दिल्ली व् मालवा के सुल्तानों के साथ लड़ी। एक बार वि।स। 1576 में मालवे के सुल्तान महमूद द्वितीय को महाराणा सांगा ने युद्ध में पकड़ लिया, परन्तु बाद में बिना कुछ लिये उसे छोड़ दिया।

मीरा बाई से सम्बंध -

महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भोजराज था, जिनका विवाह मेड़ता के राव वीरमदेव के छोटे भाई रतनसिंह की पुत्री मीराबाई के साथ हुआ था। मीराबाई मेड़ता के राव दूदा के चतुर्थ पुत्र रतनसिंह की इकलौती पुत्री थी।

बाल्यावस्था में ही उसकी माँ का देहांत हो जाने से मीराबाई को राव दूदा ने अपने पास बुला लिया और वही उसका लालन-पालन हुआ।

मीराबाई का विवाह वि।स। 1573 (ई।स। 1516) में महाराणा सांगा के कुँवर भोजराज के साथ होने के कुछ वर्षो बाद कुँवर युवराज भोजराज का देहांत हो गया। मीराबाई बचपन से ही भगवान की भक्ति में रूचि रखती थी। उनका पिता रत्नसिंह राणा सांगा और बाबर की लड़ाई में मारा गया। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद छोटा पुत्र रतनसिंह उत्तराधिकारी बना और उसकी भी वि।स। 1588(ई।स। 1531) में मरने के बाद विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। मीराबाई की अपूर्व भक्ति और भजनों की ख्याति दूर दूर तक फैल गयी थी जिससे दूर दूर से साधु संत उससे मिलने आया करते थे। इसी कारण महाराणा विक्रमादित्य उससे अप्रसन्न रहा करते और तरह तरह की तकलीफे दिया करता थे। यहाँ तक की उसने मीराबाई को मरवाने के लिए विष तक देने आदि प्रयोग भी किये, परन्तु वे निष्फल ही हुए। ऐसी स्थिति देख राव विरामदेव ने मीराबाई को मेड़ता बुला लिया। जब जोधपुर के राव मालदेव ने वीरमदेव से मेड़ता छीन लिया तब मीराबाई तीर्थयात्रा पर चली गई और द्वारकापुरी में जाकर रहने लगी। जहा वि।स। 1603(ई।स। 1546) में उनका देहांत हुआ।

खानवा का युद्ध -

बाबर सम्पूर्ण भारत को रौंदना चाहता था जबकि राणा सांगा तुर्क-अफगान राज्य के खण्डहरों के अवशेष पर एक हिन्दू राज्य की स्थापना करना चाहता थे, परिणामस्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य 17 मार्च, 1527 ई। को खानवा में युद्ध आरम्भ हुआ।

इस युद्ध में राणा सांगा का साथ महमूद लोदी दे रहे थे। युद्ध में राणा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। बाबर अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबन्ध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वा कर शराब न पीने की कसम ली, उसने मुसलमानों से 'तमगा कर' न लेने की घोषणा की। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जिसे राज्य द्वारा लगाया जाता था। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने सांगा के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। युद्ध क्षेत्र में राणा सांगा घायल हुए, पर किसी तरह अपने सहयोगियों द्वारा बचा लिए गये। कालान्तर में अपने किसी सामन्त द्वारा विष दिये जाने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने 'ग़ाजी' की उपाधि धरण की।

मृत्यु -

खानवा के युद्ध मे राणा सांगा के चेहरे पर एक तीर आकर लगा जिससे राणा मूर्छित हो गए ,परिस्थिति को समझते हुए उनके किसी विश्वास पात्र ने उन्हें मूर्छित अवस्था मे रण से दूर भिजवा दिया एवं खुद उनका मुकुट पहनकर युद्ध किया , युद्ध मे उसे भी वीरगति मिली एवं राणा की सेना भी युद्ध हार गई । युद्ध जीतने की बाद बाबर ने मेवाड़ी सेना के कटे सरो की मीनार बनवाई थी । जब राणा को होश आने के बाद यह बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए उन्होंने कहा मैं हारकर चित्तोड़ वापस नही जाऊंगा उन्होंने अपनी बची-कुची सेना को एकत्रित किया और फिर से आक्रमण करने की योजना बनाने लगे इसी बीच उनके किसी विश्वास पात्र ने उनके भोजन में विष मिला दिया ,जिससे उनकी मृत्यु हो गई ।

अस्सी घाव लगे थे तन पे । फिर भी व्यथा नहीं थी मन में ।। जय मेवाड़ ।

बेनी बाबूः राजनीति के शलाका पुरुष

✍ डॉ. अनुरुद्ध वर्मा

प्रदेश एवं देश के राजनीतिक क्षितिज पर लम्बे समय तक छाये रहे बाबू बेनी प्रसाद वर्मा का गत 27 मार्च 2920 को निधन हो गया। राजनीति में अपनी मेहनत, संघर्ष, संगठन क्षमता एवं राजनीतिक कौशल के दम पर उन्होंने ऊंचाईयां प्राप्त की। 11 फरवरी 1941 को बाराबंकी के सरौली गौसपुर में किसान परिवार में जन्मे बेनी प्रसाद वर्मा जी ने प्रारम्भिक शिक्षा गांव एवं बदोसराएँ से प्राप्त करने के बाद बीए एवं एलएलबी की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की।उन्होंने सार्वजनिक, सामाजिक जीवन की शुरूआत बुढ़वल गन्ना मिल की गन्ना यूनियन से प्रारंभ की थी। युवा, तेजतर्रार, कर्मठ एवं संगठन क्षमता के कारण 1973 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया और वह कांग्रेस की लहर के बावजूद चुनाव जीत गये। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा लगातार सफलता की सीढ़ियां पार करते रहे। आपातकाल में 1975 से लेकर 1977 तक वह संगठन को मजबूत करते रहे और आपातकाल का विरोध करते रहे। आपातकाल की समाप्ति के बाद 1977 में जनता जनता पार्टी का गठन हुआ और उनकी राजनीतिक प्रतिभा को देखते हुये पार्टी ने उन्हें उस समय की कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेत्री मोहसिना किदवई के सामने मसौली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया।चुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। जनता पार्टी नेतृत्व ने उनके संगठन कौशल को देखते हुये उन्हें पार्टी के प्रदेश महासचिव पद की जिम्मेदारी दी। बाद में उन्हें जेल एवम गन्ना जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुये कैदियों की सुविधाओं को बढ़ाया। साथ ही गन्ना किसानों का मिलों पर बकाया के भुगतान कराकर किसानों में अपार लोकप्रियता अर्जित की। उनके निर्णयों की राजनीतिक क्षेत्रों में काफी सराहना हुई।जनता पार्टी के बाद चौधरी चरण सिंह ने लोकदल का गठन किया और 1980 के विधानसभा चुनाव में असफल होने के बाद पार्टी ने उन्हें लोकदल का प्रदेश का मुख्य महासचिव बनाया और उन्होंने पूरे प्रदेश में दल को मजबूत किया। लोकदल नेतृत्व ने फिर उनपर भरोसा जताया और 1985 उन्हें मसौली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। वह भारी मतों से चुनाव जीते तथा उन्हें मंत्रिमंडल में लोक निर्माण, संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई। वह प्रदेश में मुलायम सिंह के बाद दूसरे नम्बर के ताकतवर नेता के रूप में स्थापित हुये। वर्ष 1991 में वह फिर मसौली विधानसभा से चुने गए और फिर मंत्री बने। 1996 में वह कैसरगंज से सांसद चुने गए और केंद्र में संचार राज्यमंत्री तथा बाद में कैबिनेट मंत्री बने। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूरे देश में संचार क्रांति ला दी। 1998 में वह फिर कैसरगंज से सांसद चुने गये। वर्ष 1999 में उन्होंने कौसरगंज से तीसरी बार जीत दर्ज की। बाराबंकी-कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2004 में चौदहवीं लोकसभा का चुनाव भारी मतों जीते। मुलायम सिंह यादव से मतभेदों के कारण समाजवादी पार्टी छोड़कर वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 2009 में गोंडा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर इस्पात मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के राज्य एवं कैबिनेट मंत्री बने। 2016 में कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया और वह फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये, जिसकी स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।वे कट्टर समाजवादी सोच के नेता थे। अपनी बात पर अडिग रहने वाले वर्मा जी ने अपने हिसाब से राजनीति की। बिना किसी की परवाह किये हमेशा अपनी बात बेबाकी से कहते थे। वह

(श्रद्धांजलि)

विशिष्ठ कार्यशैली वाले जमीनी नेता थे। वे लाग-लपेट वाले नेता नहीं थे, स्पष्ट बात कहते थे परंतु दिल में कुछ नहीं रखते थे। मन से बहुत उदार थे, जिसको डांट देते थे उसका काम जरूर करते थे। प्रशासनिक क्षमता के धनी बेनी प्रसाद जी केंद्र एवं राज्य के जिस भी विभाग में मंत्री रहे उस विभाग पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। सार्वजनिक कार्यों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बहुत अधिक थी। उन्होंने बाराबंकी में स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों एवं टेलीफोन का जाल बिछाकर उसे विकास की मुख्यधारा में शामिल किया। वे बाराबंकी में विकास के पर्याय थे। आखिरी समय तक वह बाराबंकी के लिए चिंतित रहे। ऐसे राजनेता का हमारे मध्य से जाना अपूरणीय राष्ट्रीय क्षति है क्योंकि उनके जैसे जनसरोकार से जुड़े नेता बार-बार जन्म नहीं लेते। विकास पुरुष के रूप में वे हमेशा याद किये जाते रहेंगे। ■

भारत को इस्लामिक देश बनाने का कुचक्र कामयाब होगा?

✍ आर.के. सिन्हा

दिल्ली के भीड़भाड़ भरे निजामउद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मुख्यालय से निकाले गए हजारों लोगों में इंडोनेशिया, मलेशिया बांग्लादेश आदि देशों के नागरिकों का होना भारतीय समाज की आंखें खोलने वाली घटना है। जमात ने तो भारत की पीठ पर वार किया है। वह तो भारत को इस तरह का घाव देना चाहता था ताकि भारत कभी उबर न सके। अब इस आशंका को ठोस आधार मिल चुका है कि तबलीगी जमात के विदेशी कार्यकर्ता भारत को कोरोना वायरस से भयंकर रूप से संक्रमित करना चाह रहे थे। यानी वे भारत की एक बड़ी आबादी को कोरोना का शिकार बनाकर यहां इस्लामिक देश बनाने का सपना देख रहे थे।

मोटा-मोटी तबलीगी जमात का लक्ष्य भारत के मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने और गैर-मुसलमानों को इस्लाम से जोड़ना ही है। यह तो कहने की बातें हैं कि तबलीगी जमात के लोग मुसलमानों को बेहतर मुसलमान बनाने के मार्ग पर लेकर जाते हैं। राजधानी की तबलीगी जमात में शामिल हजारों लोगों में से 441 में कोरोना के सक्रिय लक्षण मिले हैं। जरा सोचिए कि इन्होंने कितने हजारों या लाखों लोगों को कोरोना का शिकार बनाने का काम कर ही दिया होगा। इनकी देश और मानवता विरोधी करतूतों के कारण ही भारत सरकार और शांति प्रिय भारतीय समाज सकते में है। चिंता की एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि अभीतक कोरोना वायरस का कोई इलाज ही नहीं मिल पाया है।

बताते हैं कि हरियाणा के नूंह में 1927 में तबलीगी जमात की स्थापना की गई थी। हरियाणा के मेवात भाग में लाखों लोगों ने इस्लाम धर्म में जबरन शामिल किये जाने के बाद भी अपनी हिन्दू परंपराओं और रीति-रिवाजों को छोड़ा नहीं था। तबलीगी जमात उन्हीं लोगों को इस्लाम से और करीबी से जोड़ने में लगी थी। हालांकि हरियाणा के मुसलमान अब भी सामान्यतः हिन्दू धर्म के रीति-रिवाजों से जुड़े हुए हैं। उनमें विवाह के वक्त अब भी वर-वधू पक्ष अपने हिन्दू धर्म के गोत्र पूछता है। यानी मुसलमान बनने के बाद भी वे हिन्दू ही रहे। पर अपनी स्थापना के बाद से तबलीगी जमात का मकसद बदलता गया। अब ये प्रकट रूप में भले न सही पर नेपथ्य में गैर-मुसलमानों को मुसलमान बनाने के अभियान में ही जुटा है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। लव जिहाद इसी के शातिर षड्यंत्र की उपज है। तबलीगी जमात बीते सौ साल से तमाम इंसान को ही एक रंग और रूप में ढालने में लगा हुआ है। ये भाईचारे के लिए एकरंगी होने को जरूरी बताते हैं। एक ही रंग और रूप में अनवरत सबको रंगे जा रहे हैं। अब कहीं जाकर पकड़ में आए हैं। इनकी पोल-पट्टी खुल गई है। अब तो इन्हें कतई छोड़ा नहीं जाएगा। कम-से-कम अमित भाई शाह के गृह मंत्री और अजीत डोभाल के सुरक्षा सलाहकार रहते यह तो संभव नहीं दिखता।

कहते हैं कि तबलीगी जमात आज दुनिया के दो सौ देशों में फैली है। संगठित तरीके से देश-विदेश के कोने-कोने पर कब्ज़ा करके इस्लामिक राष्ट्र बनाने के ख्वाब पाले हैं। इन्हें लगता है कि भारत और इजराइल पर इस्लाम का परचम फहराना सबसे जरूरी है। इन दोनों देशों में इस्लाम को मानने वाले

तो हैं लेकिन इस्लाम का वर्चस्व स्थापित होने की कोई संभावना नहीं दिखती है। अगर बात भारत की करें तो ये तबलीगी जमात वाले देश के दूरदराज के सुदूर इलाकों में जाकर सीधे-सरल लोगों से कहते हैं कि वे कलमा पढ़कर इस्लाम से जुड़ें और मुसलमान बन जाएं नहीं तो मरने के बाद जहुन्नम में जलने के लिए तैयार रहें। इसके विपरीत इस्लाम में तो मौत के बाद भी एक शानदार जिंदगी इंतजार कर रही है। उस दुनिया में मौज ही मौज है। तबलीग जमात के कार्यकर्ता गांवों में जाकर प्रचार करते हैं कि भारत में बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार इस्लामी क़ानून शरीयत को लागू करने से दूर होगा न कि काफिरों के क़ानून से। अब सरकार को तबलीगी जमात के खर्चों की पड़ताल करनी होगी कि ये इतना लंबा-चौड़ा संगठन कैसे चलाते हैं? इन्हें कहां से मदद मिलती है?

अगर भारत में तलबीगी जमात गैर-मुसलमानों को इस्लाम से जोड़ना चाहता है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में यह शरीयत के हिसाब से देश की शासन व्यवस्था चलाने की मांग करता है। गिरगिट जैसा रंग बदलता रहता है यह जमात। अब इन्हीं की करतूतों के कारण पाकिस्तान में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तानी सरकार भी यह कह रही है। इन्होंने पाकिस्तान में भी कहर बरपा रखा है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में अबतक इससे जुड़े करीब दर्जनों केस आ चुके हैं। तबलीगी जमात ने पाकिस्तान की पंजाब सरकार की बात को नजरअंदाज करते हुए अपना सम्मेलन किया। यानी ये हर जगह अपना जंगलीपन दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो किया क्या जाए?

अब तो एक बात शीशे की तरह साफ होती जा रही है कि कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिये भारत सरकार को इन मानवता के दुश्मनों पर चाबुक चलानी ही होगी। यह सच है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म मानने और उसके प्रचार-प्रसार की अनुमति तो जरूर देता है। यहां तक सब वाजिब भी है। पर भारत का संविधान किसी को भारत में रहकर उसकी जड़ें खोदने का अधिकार नहीं देता। लेकिन, तबलीगी जमात यही तो कर रहा है। वे कहाँ किसी संवैधानिक सरकार की बात मानने को राजी हैं। क्या इसे माफ किया जा सकता है? कतई नहीं।

तबलीगियों ने सबकुछ जानते हुए भी जिस तरह की अक्षम्य हरकत की है, उसे माफ करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इस मसले पर देश भर में बहस हो रही है तो कुछ प्रगतिशील यह कहने से बाज नहीं आ रहे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को हिन्दू- मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। यह क्या मतलब है। यानी ये लोग तबलीगी जमात को कहीं न कहीं बचाने की फिराक में हैं। क्या सारे मुसलमान तबलीगी हैं। हरगिज नहीं। इस सारी बहस के दौरान हर्ष मंदर, राणा अयूब, कन्हैया जैसे प्रगतिशील और मौजूदा एनडीए सरकार पर हर मसले पर वार करने वाले फ़िलहाल नदारद हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) बिरादरी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या इन्हें तबलीगी जमात की हरकत के लिए उसे आड़े हाथों नहीं लेना चाहिए था। पर अगर ये इस तरह का कोई कदम उठाते तो इनकी प्रगतिशीलता खतरे में न पड़ जाती। यहां पर मैं मुसलमानों के मिडिल क्लास से भी सवाल करना चाहता हूं कि वे तबलीगी जमात के खिलाफ क्यों नहीं आवाज बुलंद करते। मात्र कुछ शिया नेताओं के किसी ने निंदा नहीं की। इन्हें तबलीगी जमात के देश को अंधकार युग में ले जाने के खिलाफ पहले से ही मोर्चा संभाल लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने इस अवसर को खो दिया। वे हमेशा की तरह अपने को विक्टिम मोड में ही रख रहे हैं। उन्हें भी इतिहास माफ नहीं करेगा।

(लेखक वरिष्ठ संपादक एवं स्तंभकार हैं।)

संक्रमण को ले कर अमेरिका और चीन में तनातनी

कोविड की मार से बेरोज़गारी और मंदी के संकेत अमेरिकी ग्रामीण गाँवों को लौट रहे हैं

ललित बंसल

दुनिया के सर्वशक्तिशाली देश अमेरिका कोविड-19 को ले कर उपहास का केंद्र बनता जा रहा है। एक विकसित देश के रूप में अपनी सारी शक्तियों के उपयोग के बावजूद अमेरिका में बुधवार की सायं तक इस अदृश्य संक्रमण से तेरह हज़ार से अधिक जानें जा चुकी हैं। एक सौ वर्षों में बेरोज़गारी के अपने निम्नतम स्तर 3.5 प्रतिशत के स्तर तक पहुँचने के क़यास लगाए जाने लगे हैं। तब बेरोज़गारी दस प्रतिशत से अधिक पहुँच गई थी। यही नहीं, स्टाक मार्केट लाल रेखा से नीचे रसातल की ओर बढ़ने से निवेशकों और बड़े उद्यमियों की स्थिति दयनीय हुई है। अमेरिका के लोग भी ग्रामीण भारत की तरह अपने-अपने गाँवों की ओर जाने लगे हैं।

बेरोज़गारी और आर्थिक पैकेज : अमेरिकी इकानमी को बदतर स्थिति में जाने से रोकने के लिए सेंट्रल बैंक फ़ेड रिज़र्व और कांग्रेस दोनों ओर से खरबों डालर के आर्थिक पैकेज से उपाय किए जा रहे हैं। इस आर्थिक पैकेज में कोविड-19 के उपचार में अरबों डालर की मदद की जा रही है। बड़े और छोटे

व्यवसायों से नौकरियों से निकाले जा चुके अथवा संक्रमण से जान बचा कर खुद घर में बैठे 66.5 लाख बेरोज़गारों को मज़दूरी भत्ते देने, छोटे व्यवसाइयों और बड़े कारपोरेट को ज़िंदा रखने के लिए सरकारी ख़ज़ाना खोल देने के सतत उपक्रम किए जा रहे हैं। अभी तक क़रीब साढ़े पाँच खरब डालर की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, तो पाँच सौ अरब डालर की स्वीकृति के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच बातचीत हो रही है। इस तरह के आर्थिक उपचार चीन सहित किसी देश ने नहीं किए हैं।

अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट बहुल प्रतिनिधि सभा में स्पीकर नैंसी पेलोसी ने बुबुधवार को एक वीडियो जारी कर सीधे-सीधे आरोप लगाया है कि ट्रम्प कोविड-19 से निपटने में विफल रहे हैं। इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ही नहीं, रिपब्लिकन नेताओं ने भी नेंसी पेलोसी की निंदा की है।

यह अदृष्य संक्रमण आया कहाँ से है? इस पर पूँजीवादी अमेरिकी विद्वत समुदाय और चीन के साम्यवादी तंत्र में परस्पर तनातनी हो गई है। दुनिया भर में इस संक्रमण से एक लाख के क़रीब जानें गँवा दिए जाने पर अमेरिकी मीडिया और विद्वत समुदाय में यह कहा जा रहा है कि वुहान (चीन) में पैदा हुआ यह संक्रमण कुदरती नहीं है, यह लेबोरेटरी जनित है। इस पर अमेरिका में प्रवासी भारतीय समुदाय से दोगुना प्रवासी चीनी समुदाय का सतत तिरस्कार हो रहा है। ट्रम्प की ओर से व्हाइट हाउस में प्रेस कॉंफ़्रेंस में कोविड-19 को चीनी संक्रमण के नाम से उच्चारण करने के बाद घृणा अपराध के मामलों में सौ गुणा वृद्धि हुई है। यह स्थिति चीनी तंत्र और वहाँ की जनता को नागवार गुज़री है। चीन ने भी आरोप लगाए हैं कि यह संक्रमण अमेरिकी सेना की ओर से लेबोरेटरी में तैयार किया गया था, जो समय पूर्व लीक हो गया। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लगाए जा रहे हैं।

डब्ल्यू एच ओ सवालों के घेरे में- डब्ल्यू एच ओ को चीन केंद्रित बता कर अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन सहित डब्ल्यू एच ओ पदाधिकारियों को हतप्रभ कर दिया। ट्रम्प ने कहा था कि वह डब्ल्यू एच ओ को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि रोक सकते हैं। इस पर बुधवार को डब्ल्यू एच ओ महानिदेशक टेडरास अधनोम गेबरएसस ने इतना कहा कि यह संक्रमण भयावह है। दुनिया भर को चाहिए कि सभी एकजुट हों। डब्ल्यू एच ओ के यूरोपीय क्षेत्रीय निदेशक हान्स क्लूज ने टिप्पणी की कि यह वक़्त परस्पर उलझने का नहीं है। हम एक घोर संकट में हैं। इस पर ट्रम्प ने बुधवार को इतना कहा कि वह ग़ौर करेंगे। यहाँ सवाल यह उठाया जा रहा है कि ट्रम्प ने यह मत क्यों व्यक्त किया? अमेरिका सदस्य देशों की ओर से दिए जाने वाले वार्षिक शुल्क दो लाख डालर के अलावा डब्ल्यू एच ओ के कुल बजट का 14 प्रतिशत अतिरिक्त फ़ंड जुटाता है। इसके विपरीत चीन अमेरिका से आधा फ़ंड दो करोड़ 80 लाख डालर स्वेच्छिक फ़ंड देता है। डब्ल्यू एच का कुल बजट चार अरब डालर प्रतिवर्ष है। इसके 194 सदस्यों में सौ सदस्य तो सदस्यता शुल्क भी नहीं दे पाते। आज डब्ल्यू एच ओ कंगाली की स्थिति में है।

ट्रम्प को डब्ल्यू एच ओ के ख़िलाफ़ कड़ा बयान क्यों देना पड़ाः अमेरिका में प्रवासी चीनी समुदाय के चालीस लाख लोग अपने महा पर्व ल्यूनर ईयर%मनाने जनवरी के तीसरे सप्ताह में चीन गए थे, जो फ़रवरी के पहले सप्ताह तक वापस अमेरिका के विभिन्न शहरों आ गए थे। वुहान में कोरोना संक्रमण के अंकुरित होने और इस महानगर की की एक करोड़ से अधिक आबादी के आधी से अधिक शंघाई, बीजिंग और अन्य चीनी शहरों में चली गई थी। न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सही माने तो इन चालीस लाख लोगों में ज़्यादातर न्यू यॉर्क के थे। डब्ल्यू एच ओ की ओर से ग़लती यह हुई कि दिसंबर के अंत तक वह इस संक्रमण को निमोनिया कहती रही। उसने 30 जनवरी को ग्लोबल हेल्थ इमेर्जेंसी घोषित किया और फिर फिर 11 मार्च को वैश्विक महामारी का नाम दिया। इस बीच लाखों लोग सैकड़ों विमान सेवाओं से वापस अमेरिका आ चुके थे और चालीस हज़ार लोग अमेरिका से बाहर भी गए थे।

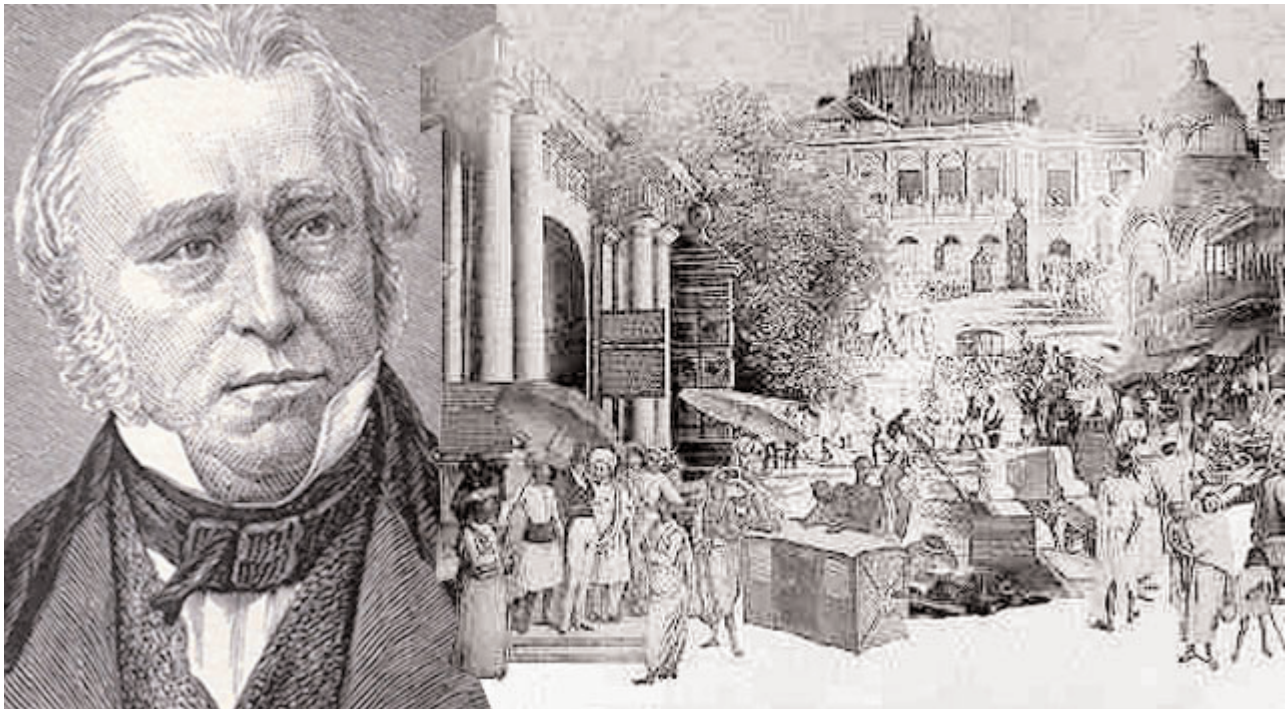

भारतीय परंपराओं एवं जीवन मूल्यों में छिपे रक्षा कवच

✍ **डॉ. मोक्षराज**

लॉर्ड मैकाले चाहता था कि भारत की शिक्षा नीति ऐसी बने कि जिसके प्रसार से भारतीय लोग अपनी संस्कृति व सभ्यता से ग्लानि करने लगें तथा उस पद्धति से पढ़े-लिखे भारतीय लोग अंग्रेजों की जीवनशैली को बेहतर मानें। वेदों के जर्मन विद्वान् प्रो. मैक्समूलर का लक्ष्य था भारतीय अपनी संस्कृति से घृणा करें। ब्रिटेन फूट डालकर भारत को गुलाम बनाये रखना तथा उसके सभी संसाधनों-खजानों पर उनका कब्जा जमाना चाहता था। मुगल तलवार व जेहाद के बल पर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। चर्च चालाकी, लालच व चमत्कार के पाखंड से भोले लोगों को भ्रमित कर धर्मान्तरित करने के मंसूबों पर काम कर रहा था। वस्तुतः ये सभी मतवादी ऐसा पाप कर रहे थे कि जिससे विश्व के सभी मानव संकट में पड़ सकते थे। आज यदि भारत में आर्य संस्कृति की परंपरा नष्ट हो चुकी होती तो न संसार में योग, प्राणायाम-ध्यान की परंपरा रहती न दाह-संस्कार की वैज्ञानिक पद्धति, न नमस्ते करने की रीति होती न शाकाहारी भोजन बनाने के सैकड़ों ढंग बच पाते और न ही गोत्र प्रणाली के निर्वाह से आनुवांशिकी (जेनेटिक) विकास का विज्ञान समझ आता।

कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, प्लेग, एचआईवी-एड्स जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियाँ तथा ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु रेडिएशन, पर्यावरण प्रदूषण, कैंसर, मधुमेह और जैनेटिक बीमारियाँ विश्व की बड़ी समस्याओं में गिनी जाती हैं। तनाव, एकाकीपन, आत्महत्या, नशा एवं हिंसा की प्रवृत्ति भी इन्हीं में सम्मिलित की जा सकती हैं। इन सभी के समाधान की दृष्टि से यदि हम 40 वर्ष पहले के किसी भी भारतीय गाँव को देखें तो अनेक उपाय हमारे सामने होंगे। खाद के लिए कूड़े व गोबर के ढेर, कंडे (छाने) राख, तालाब, कुँए, बावड़ी, चौपाल, गाय-भैंस, भेड़-बकरी वाले गाँव के बाहर अखाड़ा, साधु-संतों की बगीची, रामलीला, हवन, वेदपाठ, दशहरा एवं होली के आयोजन व संयुक्त परिवार थे। अभिवादन के रूप में हाथ जोड़कर नमस्ते या राम-राम करते थे। उत्तम स्वास्थ्य की अवस्था में चरण स्पर्श या गले मिलने की भी परंपरा थी। लिपा हुआ आँगन, चौका से बाहर ही पादुका उतारने का संस्कार, पूर्णिमा-अमावस्या पर खीर, ब्राह्मणों को भोजन अंगारों पर ही घी-भात या खीर के भोग की भीनी-भीनी सुगंधी, बड़ों के प्रति सम्मान व उत्साह से भरा कर्त्तव्य भाव था। किसी भी मोहल्ले विरादरी की कन्या के विवाह का प्रबंध विलक्षण था। प्रत्येक ग्रामवासी उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर श्रद्धा से कन्यादान करता था। छह गोत्र बचाकर विवाह किया जाता था। प्रायः सभी दम्पति एक पति व एक पत्नीव्रत में बँधकर निष्ठा से जीते थे।

किसी भी भारतीय परंपरा के गाँव का यह चित्र दुनिया की सभी समस्याओं के समाधान के लिए ब्लू प्रिंट हो सकता है। उनकी सादगी व सरलता का यह दर्शन प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम को

व्यक्त करता है। जहाँ के घर मिट्टी व गोबर से इसलिए बने होते थे ताकि देवता तुल्य पहाड़-पर्वतों का प्राकृतिक सौन्दर्य बचा रह सके। गोबर से लिपे मिट्टी के घरों पर रेडिएशन का प्रभाव भी नगण्य होता है। जैविक खेती एवं श्रम की संस्कृति के कारण कैंसर-मधुमेह नहीं था। राख, अपामार्ग, बबूल व नीम के प्रयोग से बुढ़ापे में भी दाँतों की बीमारियां नहीं थी। मच्छर न होने से मलेरिया केवल शहरों तक सीमित था। बैठकर पानी पीना व भोजन करना तथा बैठकर लघुशंका करना आदि कुछ ऐसे सद् व्यवहार हैं, जिनके औचित्य पर आधुनिक विज्ञान या पाश्चात्यों का ठप्पा लगना शेष है । पनघट का संवाद व अखाड़ों में जोर-आज़माइश के चलते एवं योग, प्राणायाम, ध्यान, भक्ति के कारण आत्महत्या, तनाव, एकाकीपन की समस्या न के बराबर थी। विशाल स्तर पर होलिका दहन व यज्ञ होते थे। अंत्येष्टि (दाह संस्कार) के लिए प्रत्येक घर से समिधास्वरूप कंडे या लकड़ी इकट्ठी हो जाती थी। स्वच्छता व शुद्धि के साथ नित्य-नैमित्तिक यज्ञ होते थे, वहाँ कोरोना, स्वाइन फ्लू, एड्स जैसे संक्रामक रोग केवल बाहर के देशों से ही आ सकते हैं।

चींटियों तक को बचाकर चलना और मीठा आटा (पंजीरी) खिलाना, सब प्राणियों में अपने समान आत्मा मानकर जीने वाले अधिकांश लोग शाकाहारी ही थे। आयुर्वेदिक, श्रौत व स्मार्त ग्रन्थों के आधार पर किए जाने वाले हवन व शाकाहार के गुण ग्लोबल वार्मिंग एवं पर्यावरण संतुलन के लिए अभूतपूर्व उपाय हैं। आजकल धूल-धूप व जीव जन्तुओं के संपर्क मात्र से तथा भोजन में ग्लूटन, मूंगफली से भाँति-भाँति की एलर्जी हो रही है। मानसिक अवसाद, पागलपन जैसी अनेक बीमारियों ने करोड़ों विदेशियों का जीवन नरक बना दिया है। यदि वर्णसंकर एवं स्वगोत्रीय विवाह न होते तो इतनी जेनेटिक बीमारियाँ उत्पन्न ही नहीं होती।

भारत की वैज्ञानिक परंपराओं की रक्षा एवं उनके मूलभूत सिद्धान्तों को जीवित रखने के लिए 145 वर्ष पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने ÷वेदों की ओर लौटो का नारा देकर आर्यसमाज रूपी आंदोलन चलाया। उन्होंने यह भी कहा कि शव को धरती में गाढ़ने से जल, वायु एवं भूमि तो प्रदूषित होते ही हैं, कृषि-पशुपालन शिक्षा एवं उद्योग धंधों में काम आने योग्य भूमि धार्मिक पाखंड के कारण अनुपयोगी व रोग उत्पन्न करने वाली हो जाती है। अतः उन्होंने संस्कार विधि में अंत्येष्टि की विधि लिखी। भारत के रीति-रिवाज़ एवं जीवन मूल्य न केवल संपूर्ण मानव जाति के लिए बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए भी रक्षा कवच हैं।

जिसको मिटाने में सदियाँ गँवाईं, मुमकिन नहीं पर उसे अब मिटाना।

(लेखक वॉशिंगटन डीसी में भारतीय संस्कृति शिक्षक हैं।)

खत्म हों फाँसी टालने के कानूनी विकल्प

प्रमोद भार्गव

आखिरकार निर्भया दुष्कर्म से जुड़े दरिंदों को फांसी हो गई। इससे जहां मानव संवेदनशीलता से जुड़े लोगों को राहत मिली, वहीं तथाकथित मानवाधिकारवादी दुखी भी हुए। लेकिन अब किसी की परवाह किए बिना दुष्कर्म व हत्या और देशद्रोह जैसे मामलों में उन विकल्पों को खत्म करने की जरूरत है, जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाने के बावजूद फांसी टालने के लिए रिव्यू एवं क्यूरेटिव याचिकाएं और फिर उनके निपटारे के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करते रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि दोषियों को कानूनी विकल्प मौजूद रहने तक सजा नहीं दी जा सकती। अलबत्ता यह सही है कि भारत की न्याय वयवस्था अंतिम समय तक मृत्युदंड पाए दोषी को अपना बचाव करने का विकल्प देती है। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मृत्युदंड को लंबे समय तक टाला जाता रहे। इस परिप्रेक्ष्य में दोषियों के वकीलों को भी यह सोचने की जरूरत है कि फांसी को लटकाने के उपाय करना, न्यायालय का समय जाया करने के अलावा कुछ नहीं है।

दुष्कर्म व हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए कानून तो सख्त बन गया लेकिन परिणाममूलक नहीं निकला। जबकि बलात्कार और फिर हत्या के मामलों को जल्द निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर त्वरित न्यायालय भी अस्तित्व में आ गए हैं। कई न्यायालयों ने ऐसे जघन्य अपराधों में निर्णय दो से चार माह के भीतर सुना दिए। लेकिन अपील के प्रावधानों के चलते, उच्च व उच्चतम न्यायालयों और फिर राज्यपाल व राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दाखिल करने की सुविधा के कारण इन मामलों का वही हश्र हो रहा है, जैसा अमूमन सामान्य प्रकरण में होता है। शायद इसी परिप्रेक्ष्य में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा था कि 'जो व्यक्ति जघन्य दुष्कृत्य कर सकता है, उसका उम्र से क्या लेना-देना? फास्ट ट्रैक के बाद भी अपील पर अपील की इतनी लंबी प्रक्रिया है कि मामले के निराकरण की उम्मीद समाप्त जैसी हो जाती है। क्या ऐसे लोगों पर दया करनी चाहिए? अदालत से सजा मिलने के बाद राज्य सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय और फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने की सुविधा क्यों है?' नायडू ने यह सवाल उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए उठाया था। इसके बाद हैदराबाद की पशु चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या के आरोपियों को कथित मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कहना पड़ा था कि 'पॉक्सो कानून के तहत दुष्कर्म के दोषियों को दया याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। संसद को दया याचिका के प्रावधान पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।' लिहाजा संसद का दायित्व बनता है कि वह इस प्रश्न पर विधेयक लाए और विचार-विमर्श के बाद दया याचिका की सुविधा का रोड़ा खत्म करे। इस सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ फांसी की सजा पाए आतंकवादी और बलात्कारी उठा रहे हैं।

दरअसल जघन्य से जघन्यतम अपराधों में त्वरित न्याय की तो जरूरत है ही, दया याचिका पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की जरूरत भी है। शीर्ष न्यायालय ने यह तो कहा है कि दया याचिका पर तुरंत फैसला हो, लेकिन राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए क्या समय सीमा होनी चाहिए, यह सुनिश्चित नहीं किया। क्योंकि अक्सर राष्ट्रपति दया याचिकाओं पर निर्णय या तो टालते हैं या

फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलते हैं। हालांकि महामहिम प्रणब मुखर्जी इस दृष्टि से अपवाद रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद अफजल गुरू और अजमल कसाब की दया याचिकाएं उन्होंने ही खारिज करते हुए, इन देशद्रोहियों को फांसी के फंदे पर लटकाने का रास्ता साफ किया था। जबकि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने या तो दया याचिकाएं टालीं या मौत की सजा को उम्रकैद में बदला। यहां तक कि उन्होंने महिला होने के बावजूद बलात्कार जैसे दुष्कर्म में फांसी पाए पांच आरोपियों की सजा आजीवन कारावास में बदली।

किसी भी देश के उदारवादी लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था आंख के बदले आंख या हाथ के बदले हाथ जैसी प्रतिशोधात्मक मानसिकता से नहीं चलाई जा सकती। लेकिन जिन देशों में मृत्युदंड का प्रावधान है, वहां यह मुद्दा हमेशा ही विवादित रहता है कि आखिर मृत्युदंड सुनने का तार्किक आधार क्या हो? इसीलिए भारतीय न्याय व्यवस्था में लचीला रुख अपनाते हुए गंभीर अपराधों में उम्रकैद एक नियम और मृत्युदंड अपवाद है। इसीलिए देश की शीर्षस्थ अदालतें इस सिद्धांत को महत्व देती हैं कि अपराध की स्थिति किस मानसिक परिस्थिति में उत्पन्न हुई? अपराधी की सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों व मजबूरियों का भी ख्याल रखा जाता है। क्योंकि एक सामान्य नागरिक सामाजिक संबंधों की जिम्मेदारियों से भी जुड़ा होता है। ऐसे में जब वह अपनी बहन, बेटी या पत्नी को बलात्कार जैसे दुष्कर्म का शिकार होते देखता है तो आवेश में आकर हत्या तक कर डालता है। भूख, गरीबी और कर्ज की असहाय पीड़ा भोग रहे व्यक्ति भी अपने परिजनों को इस जलालत की जिंदगी से मुक्ति का उपाय हत्या में तलाशने को विवश हो जाते हैं। जाहिर है, ऐसे मजबूरों को मौत की सजा के बजाय सुधार और पुनर्वास के अवसर मिलने चाहिए क्योंकि जटिल होते जा रहे समय में दंड के प्रावधानों को तात्कालिक परिस्थिति और दोषी की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी आंकना जरूरी है। परंतु बलात्कार और फिर महिला की हत्या भिन्न प्रकृति के अपराध हैं।

दया याचिका पर सुनवाई के लिए यह मांग हमारे यहां उठ रही है कि इसकी सुनवाई का अधिकार अकेले राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में न हो? इस बाबत एक बहुसदस्यीय जूरी का गठन हो। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, उप राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और कुछ अन्य विशेषाधिकार संपन्न लोग भी शमिल हों? यदि इस जूरी में भी सहमति न बने तो इसे दोबारा शीर्ष अदालत के पास प्रेसिडेंशियल रेंफरेंस के लिए भेज देना चाहिए। इससे गलती की गुंजाइश न्यूनतम हो सकती है। इसके उलट एक विचार यह भी है कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का प्रावधान खत्म करके सुप्रीम्र कोर्ट के फैसले को ही अंतिम फैसला माना जाए? यह विचार ज्यादा तार्किक है क्योंकि न्यायालय अपराध की प्रकृति, अपराधी की प्रवृति और परिस्थिति के विश्लेषण के तर्कों से सीधे रूबरू होती है। फरियादी का पक्ष भी अदालत के समक्ष रखा जाता है। जबकि राष्ट्रपति के पास दया याचिका पर विचार का एकांगी पहलू होता है। जाहिर है न्यायालय के पास अपराध और उससे जुड़े दंड को देखने के कहीं ज्यादा साक्ष्यजन्य पहलू होते हैं। लिहाजा तर्कसंगत उदारता अदालत ठीक से बरत सकती है? ■

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

जानें क्यों पक्षियों की तरह फडफड़ा रहें हैं हम ?

✍ **अरविंद कुमार**

पक्षियों को पालने का शौक अमूमन कई लोगो में देखने को मिल जाता हैं। पक्षी पालना बुरी बात नहीं हैं मगर पक्षियों को पिंजरे में बंद करके पालना एक अपराध ही हैं ऐसा अगर आप किसी पक्षीपालक को बोल दे तो वह आपको अपने दुश्मन से कम नहीं मानता हैं। हो सकता हैं साथ ही आप पर हाथ भी साफ कर दे, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके पालने वाले इस अपराध को , अपराध नही मानते हैं और तरह तरह के पक्षियों को पालते हैं ये पक्षीपालक इनके खाने पीने के समय का कैसे पालन करते हैं। क्या खाना इनको देते हैं यह सब इन की मर्जी पर निर्भर हैं, क्योकि पिंजरे में बंद यह पक्षी तो अपने मालिक को ना ही कुछ बोल सकते हैं न ही अपनी मर्जी का भोजन मांग सकते हैं, ऐसे में अगर इनका मालिक किसी कारण इनको खाना (दाना) देना भूल जाए या ना भी दे तो ये बेजुबान तो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते ।

खुले गंगन के ये आजाद परिंदे कभी अपनी कैद का रोना नही रो पाते हैं, अपनी कैद के कारण ये पक्षी समय से पहले ही दम तोड़ देते हैं। मगर शौक बड़ी चीज हैं ऐसी कहावतो के सामने इन पक्षियों का दर्द कुछ भी नहीं हैं शायद। आज जब देश में कोरोना संक्रमण की वजह से देश में लॉक डाउन चल रहा हैं। हम लोगों को संक्रमण से बचने के लिए, घरों में ही रहना हैं, तो फिर भी हम पिंजरे में बंद पक्षियों की तरह ही फडफडा रहें हैं, जबकि पिंजरे में कैद पक्षियों के फडफडाने पर हम खुश होते हैं। अगर इन पक्षियों की जगह हम अपने आप को रख कर देखेंगे तो क्या हम पर कोई ऐसा कोई अत्याचार हो रहा हैं जैसे हम इन पक्षियों पर करते हैं, न बल्कि हम इन पक्षियों को अपने मन चाहे आकार के पिंजरे में कैद करके रखते हैं ।

आज जब लॉकडाउन हैं तो हम लोगों को अपने उन घरों में रहने में तकलीफ क्यो हो रहीं हैं जिनको हमने ही अपनी सुविधानुसार बनवाया हैं ? हमें हमारे मन पसंद खाने की आजादी भी हैं, सुबह शाम जरूरत की वस्तुए भी खरीद पा रहे हैं, अपने परिजनों के बीच रह रहें हैं, लेकिन फिर भी हमें लॉकडाउन सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रहीं हैं , आखिर हम मानव इतने स्वार्थी और अनुशासनहीनता के परिचायक क्यो बनें हैं ? यह पता होते हुए भी की हम पर कुछ दिन के लिए कुछ पांबदिया लगीं हैं न की हम किसी पिंजरे मैं कैद है जिसमें हम पक्षियो को कैद करके रखते हैं ।

फिर क्यो हम लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहें? यदि हम मानव जाति पर मंडरा रहे कोरोना वायरस के खतरे को जानते हुए भी हम घरों में नहीं रह सकते तो हम उन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे कैद करके क्यो रखते जिसका हक हमें हैं ही नहीं ? ■

कोरोना काल : मनरेगा में ग्राम प्रधानों का गड़बड़झाला

✍ रमेश ठाकुर

कोरोना संकट की मार से वैसे तो सभी बेहाल हैं लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो सबसे ज्यादा आहत हुआ है। वह वर्ग है दिहाड़ी मजदूर। उनके समक्ष रोजाना पेट पालने की मुश्किल चुनौती है। कोरोना की वजह से मौजूदा संकटकाल में कमोबेश ऐसी ही समस्या से मेहनतकश गुजर रहे हैं। लॉकडाउन से उनके सामने बड़ा संकट है। बात रोजी-रोटी पर आ गई है। हालांकि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा उनके खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरतों आदि की उचित व्यवस्था की हुई है। पर, विडंबना यह है कि इस भयावह दौर में भी इस व्यवस्था में भ्रष्टाचारियों ने सेंध लगा दी है। मनरेगा रोजगार देश के मजदूरों को बड़ी राहत देता है।हिंदुस्तान के ज्यादातर गांवों में दिहाड़ी मजदूरों की बड़ी आबादी है। बीते एक दशक से गांव के मजदूर केंद्र सरकार की बहुआयामी योजना मनरेगा से जुड़े हैं।

गांव छोड़कर जो मजदूर शहरों में चले गए थे, वह लॉकडाउन के बाद अपने-अपने गांव पहुंच गए हैं। लॉकडाउन से उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी मनरेगा मजदूरों को एडवांस और अतिरिक्त धनराशि आवंटित कर दी है। लेकिन, उस धनराशि पर ग्राम प्रधानों की गिद्ध नजर पड़ गई है। नजर ऐसी जिससे वह धन आसानी से मजदूरों तक नहीं पहुंचने पाए। प्रधानों का यह तिकड़मी रवैया निश्चित रूप से केंद्र सरकार के मानवीय संकट के वक्त मजदूरों को उबारने के प्रयासों पर धक्का है। ग्राम प्रधान, रोजगार सेवकों, सचिवों और विकास खंड अधिकारियों ने पलीता लगा दिया है।बहुत दुखद है कि संकट के समय भी कुछ लोग अमानवीय हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे वक्त में भी उनके दिमाग में सिर्फ लूट-खसोट पनपती है। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की कमाई पर भी डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं।

उसी कड़ी में मनरेगा धन में सेंधमारी का एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी पर डाका डालने की कोशिश की गई। मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का है। मजदूरों के खून-पसीने की कमाई को हड़प करने के प्रयास हुए। प्रयास किसी और नहीं, बल्कि गांव के प्रधान द्वारा किया गया। उसकी होशियारी उस वक्त धरी रह गई, जब रकम डकारने से पहले ही प्रधानपति को जिलाधिकारी ने जेल की हवा खिलवा दी। मजदूरों के पैसों के गड़बड़झाले की शिकायत जब डीएम के पास पहुंची, उन्होंने जांच की तो लाखों की हेरफेर पकड़ में आयी। डीएम के आदेश पर तुरंत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा।मनरेगा के पैसों में भ्रष्टाचार का बड़ा तंत्र मिलकर काम करता है। प्रधान से लेकर जिले के कई आलाधिकारी इसमें लिप्त होते हैं।

अगर सख्ती होती तो कोरोना संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि पर ये लुटेर सेंध नहीं मार पाते। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने समूचे हिंदुस्तान के गरीबों, वृद्धों, मनरेगा मजदूरों, असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों व समाज के अन्य जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार का मकसद मात्र इतना है कि शायद उनके द्वारा दी जाने वाली सहयता से गरीबों की मुश्किल कुछ कम हो। काम-धंधे ठप होने से दिहाड़ी-मजदूर ज्यादा परेशान न हों इसलिए समय पर उनको मनरेगा की दिहाड़ी मिल सके। पर, उसमें भी लुटेरों का रैकेट सक्रिय हो गया।भ्रष्टाचार का यह गठजोड़ प्रशासन की नाक के नीचे ग्राम पंचायतों के लिए विकास फंड और मनरेगा में आवंटित धनराशि में जमकर घपला करते हैं।

ग्राम प्रधान अपना, अपनी पत्नी व नाबालिग पुत्र-पुत्रियों का गलत तरीके से जॉबकार्ड बनाकर बिना काम करे हजारों रुपये उनके बैंक खातों में डालवाकर हड़पने जैसी अनगिनत शिकायतें जिला प्रशासन और सरकारों को रोजाना मिल रही हैं। प्रधानों की बैंकों से साठगांठ होती। जब भी मजदूरों का पैसा बैंक में आता है तो प्रधान सभी मनरेगा मजदूरों का बैंक पास लेकर बैंक पहुंच जाते हैं। बैंक मैनेजर का भी चढ़ावा तय होता है इसलिए पैसे निकालने में परेशानी नहीं होती। यूपी के जौनपुर में पिछले सप्ताह एक प्रधान कुछ इसी तरह से धरा गया। प्रधानपति मनरेगा मजदूर को बिना बताये उसका पैसा निकालने बैंक पहुंचा, पैसे निकाल भी चुका था लेकिन समय पर धर लिया गया।

डीएम डीके सिंह ने प्रधान को मनरेगा का पैसा गलत तरीके से निकालने के आरोप में बैंक से ही सीधे जेल भिजवा दिया। मनरेगा के भ्रष्टाचार में कोई एक प्रदेश नहीं, सभी प्रदेशों में इस तरह की शिकायतें हैं।मनरेगा और ग्राम योजनाओं में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है इसकी जानकारी प्रदेश सरकारों को भी होती है। समाधान के तौर पर हुई कागजी कार्यवाही इसे रोकने में अबतक नाकाफी साबित हुई है। ग्राम विकास योजनाओं में सरकार द्वारा भेजे जाने वाले पैसों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई प्रयास हुए, अन्ततः उतनी सफलता नहीं मिली, जिसकी उम्मीद थी। हालांकि योजनाओं का पैसे सीधे पात्रों के बैंक खातों में जाता है लेकिन उसमें भी ग्राम प्रधान दीमक की तरह लग जाते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं) ■

मप्रः गहराएगा कोरोना संकट ?

✍ **सतीश एलिया**

मध्य प्रदेश में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के कारण कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई की जो कमजोर तैयारी बीते माह के आखिरी दिनों में हुई, उसका नतीजा प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की बढ़ोतरी के रूप में सामने आ रहा है। करीब एक पखवाड़ा पहले मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान अकेले ही करीब ढाई दर्जन मंत्रियों का काम कर रहे हैं। कई बड़े अफसर और मैदानी अफसरों की बदली से भी हालात कठिन होते गए। इसके बाद से मुख्यमंत्री लगातार कोरोना पर पूरी तरह से सरकार और शासन को केंद्रित किए हुए हैं लेकिन नौकरशाही के फैसलों और जानकारियां जाहिर नहीं करने के चलते स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव, संचालक, अपर संचालक से लेकर कई अफसर व कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके पीछे अहम कारण उनमें से कुछ के परिवारों के सदस्यों का अमेरिका जैसे कोरोना प्रभावित देशों से आने की जानकारी के बावजूद इन अफसरों का खुद को क्वारंटीन करने के बजाय सरकारी कामकाज में जुटे रहना और परिवार की ट्रैवल हिस्ट्री को अपने तक ही सीमित रखने जैसी गंभीर लापरवाही शामिल है।

सरकार चलाने में होती सहूलियत

मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी 230 में से 24 सीटें रिक्त हैं। यानी वर्तमान में 206 विधायक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में विधायक संख्या के 15 फीसदी यानी 29 मंत्री हो सकते हैं। कोराना संकटकाल में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, नगरीय प्रशासन, होम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, श्रम समेत करीब एक दर्जन ऐसे महकमे हैं, जिनमें समन्वय और प्रशासन चुस्ती आवश्यक है। पूरा मंत्रिमंडल भले न सही लेकिन एक दर्जन मंत्री बनाए जाते तो बेहतर काम हो सकता था। वर्तमान में अकेले मुख्यमंत्री समूची सरकार की तरह दिन-रात जूझ रहे हैं। तंत्र का आलम यह है कि 21 के टोटल लॉकडाउन में भी राजधानी भोपाल समेत ज्यादातर शहरों व कस्बों में इसका उल्लंघन होता रहा। कोरोना संक्रमण के फैलाव की आशंका के चलते अब मंगलवार से सख्त लॉकडाउन के निर्देश दिए गए हैं।

बेचैन हैं भाजपा के वरिष्ठ विधायक

भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट में महत्वपूर्ण किरदार थे लेकिन भारी सक्रियता के बाद अचानक कोरोना संकट में कोई सक्रिय भूमिका न मिलने से बीते एक पखवाड़े से वे अपने घर में नाती-पोतों के साथ खेलते, गायों की सेवा करते और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया के हालचाल जानते हुए न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और मंत्री रहे गोपाल भार्गव भी यदाकदा टीवी चैनलों पर दिखते हैं। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अकेले ऐसे नेता हैं जो शिवराज की ही तरह खबरों में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ एक महीने पहले तक बतौर मंत्री भारी सक्रिय रहे सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री दल बदलकर विधायक भी नहीं रहे लेकिन अब वे भी निष्क्रियता के इस दौर में परेशान हैं। यह बेचैनी यदाकदा सोशल मीडिया या प्रादेशिक न्यूज चैनलों में उनकी सक्रियता में दिखती रहती है।

जमातियों की खोज खबर रखने में विफल

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से मरकज की जमात से मप्र लौटे लोगों में जमातियों की तादाद तो बताई जाती रही लेकिन वे कहां-कहां गए, यह एक हफ्ते बाद भी पूरी तरह पता नहीं है। कई जमाती छोटे-छोटे कस्बों जिनमें तहसील मुख्यालय शामिल हैं,

पहुंचे थे और वे वहां मस्जिदों और घरों में भी रुके बताए गए हैं। विदिशा जिले के सिरोंज में एक कोरोना पॉजिटव पाए जाने के बाद अब अन्य कस्बों में भी जमातियों के आने, रुकने और चले जाने की खबरों से लोगों में दहशत है। यह दहशत अब गांवों तक पहुंच रही है। लेकिन सरकारी तंत्र का इंटेलीजेंस फेल रहा है।

विदेश से लौटे लोगों की सूची के बाद भी ट्रैकिंग नहीं

करीब एक पखवाड़े पहले सूची जारी होने के बावजूद विदेश यात्रा की हिस्ट्री वाले परिवारों की जांच नहीं की गई। अकेले भोपाल शहर में ऐसे लोगों की सूची 71 पेज की थी। इनमें अब कोरोना पॉजिटिव पाई गई स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल का पुत्र तथा स्वास्थ्य विभाग की अपर संचलक वीणा सिन्हा का पुत्र भी शामिल था। यह अफसर न केवल मुख्यमंत्री के साथ बल्कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों, डॉक्टरों तथा अन्य स्टाफ के संपर्क में सतत बने रहे। अब यह आशंका गहरा रही है कि अकेले स्वास्थ्य महकमे के एक दर्जन अफसर आदि कोरोना पॉजिटव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में रह चुके कितने लोगों को यह वायरस संक्रमण सामने आ सकता है? चौंकाने वाली बात यह भी है कि स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव ने खुद को किसी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने से साफ इनकार किया और उन्होंने घर पर ही इलाज के इंतजाम कराए। इस दौरान वे घर से ही मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा में शामिल हो रही हैं, इसके लिए उनके बंगले पर अधिकारी-कर्मचारी भी जाते रहे।

खतरे की आशंका के बीच लापरवाही जारी

बीते तीन माह में भोपाल के अलावा अन्य जिलों तक अमेरिका, इटली, दुबई, ब्रिटेन आदि से यात्रा कर लौटे लोगों की अबतक न तो पहचान की कई है और न ही जांच, वह भी आधिकारिक सूची उपलब्ध होने के बावजूद। इनके संपर्क में रहे हजारों लोग अब खुद की सेहत को लेकर चिंतित हैं। आंकड़ों में अभीतक मप्र देश में नौवें क्रम पर है। यहां 256 मामले सामने आ चुके हैं, इनमें से 230 कोरोना पॉजिटिव में से 15 की मौत हो चुकी है, जबकि 11 ठीक भी हो चुके हैं।

मध्य प्रदेश : मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट हुई तेज

✍ देवदत्त दुबे

मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज हो गई है। 14 अप्रैल को लाक डाउन अवधि समाप्त हो रही है। आगे लॉक डाउन अवधि बढ़ने के पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। विपक्षी दल कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि प्रदेश में बिना मंत्रियों के सरकार चल रही है। जिससे अव्यवस्था बढ़ रही है सिंधिया समर्थक भी मंत्री बनने बेताब क्योंकि उन्हें फिर विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ना है।

दरअसल कोरोना महामारी पूरे विश्व का कैलेंडर गड़बड़ा दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है की हवाई जहाज रेल सुविधाएं ठप पड़ी है। देश में लॉक डाउन के लागू होते ही जो जहां था वहीं रह गया। अधिकांश देशवासी घरों के अंदर है ।

प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। यही कारण है कि अब मंत्रिमंडल गठन का दबाव बढ़ रहा है। खासकर मोर्चे पर डटे विभागों के मंत्रियों की अनिवार्यता बताई जा रही है। लेकिन मंत्रिमंडल गठन करना आसान नहीं है। कांग्रेस के बागी विधायकों जिनमें सिंधिया समर्थक अधिकांश है लगभग 10 से 12 मंत्री बनाए जाने है। जबकि भाजपा में लगभग 50 विधायक ऐसे हैं जो शपथ लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में लगभग 30 मंत्रियों का चयन करना बेहद कठिन कार्य है चौथी बार मुख्यमंत्री बने चौहान की असली अग्निपरीक्षा मंत्रिमंडल गठन के साथ ही शुरू हो जाएगी। विपक्षी दल कांग्रेस इस कारण मंत्रिमंडल गठन पर दबाव बना रही है। उसे उम्मीद है जिस मंत्रिमंडल गठन के कारण उनकी सरकार गई है वही मंत्रिमंडल गठन भाजपा के गले की हड्डी भी बनेगा। कम से कम चौहान के लिए काम करना इतना आसान नहीं रहेगा। जितना कि उन्हें पिछले 3 कार्यकाल में मिला था। तब प्रदेश में कांग्रेश भी कमजोर थी और भाजपा मैं शिवराज का एकछत्र राज्य था। संगठन और सरकार में उन्हें कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है प्रदेश में विधायकों को दलबदल का चस्का भी लग गया है। खासकर जिस तरह से सिंधिया समर्थक विधायकों का मंत्री बनना तय है उतना भाजपा के विधायकों का नहीं।

कुल मिलाकर कोरोना महामारी से सामूहिक रूप से निपटने के लिए

मंत्रिमंडल का गठन अनिवार्य होता जा रहा है, जिससे कि स्वास्थ्य और गृहमंत्री विभागों के काम संभाल सकें साथ ही 15 अप्रैल से गेहूं उपार्जन की घोषणा मुख्यमंत्री चौहान कर चुके हैं। इसके लिए कृषि मंत्री का भी होना जरूरी है और जिलों में जनप्रतिनिधियों भागीदारी भी जरूरी मानी जा रही है। तमाम राजनीतिक हालात मंत्रिमंडल गठन इशारे कर रहे यदि पार्टी हाईकमान से मंजूरी मिल गई।

कुल मिलाकर कोरोना महामारी से सामूहिक रूप से निपटने के लिए मंत्रिमंडल का गठन अनिवार्य होता जा रहा है। जिससे कि स्वास्थ्य और गृहमंत्री विभागों के काम संभाल सकें साथ ही 15 अप्रैल से गेहूं उपार्जन की घोषणा मुख्यमंत्री चौहान कर चुके हैं। इसके लिए कृषि मंत्री का भी होना जरूरी है और जिलों में जनप्रतिनिधियों भागीदारी भी जरूरी मानी जा रही है तमाम राजनीतिक हालात मंत्रिमंडल गठन इशारे कर रहे यदि पार्टी हाईकमान से मंजूरी मिल गई तो फिर 15 अप्रैल या इसके बाद कभी भी मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द कर सकते हैं मंत्रिमंडल का गठन

भोपाल। मध्यप्रदेश की चौथी बार कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपने मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 अप्रैल तक मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। दरअसल, लॉकडाउन के प्रथम चरण के 21 दिन पूरे होने वाले हैं और द्वितीय चरण के लिए आम सहमति बन गई है। ऐसे में समझा जा रहा है कि सीएम मंत्रिमंडल का गठन कर देंगे।

जानकारी के अनुसार, शिवराज पहले चरण में लगभग 25 से 28 लोगों को मंत्री बना सकते हैं। इन मंत्रियों को कोरोना वायरस संक्रमित जिलों की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है और वही जाकर कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कहा जा सकता हैं।

उल्लेखनीय है कि 23 मार्च को शिवराज सिंह ने अकेले शपथ ली थी और तब से अब तक वो अकेले ही सरकार चला रहे हैं। इधर, भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस लगातार मंत्रिमंडल गठन को लेकर सवाल उठा रही हैं। शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है, आए दिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में लगातार बढ़ते दवाब के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना जताई जा रही हैं। माना जा रहा है शिवराज 15 अप्रैल तक विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा 15 अप्रैल से मध्यप्रदेश में गेहूं की खरीदी भी शुरू होने वाली है और ऐसे में जनप्रतिनिधियों का सक्रिय होना बेहद जरूरी हैं।

शिवराज मंत्रिमंडल में पहले दस स्थान सिंधिया समर्थक विधायकों के लिए तय है, जिनमें प्रभुराम चौधरी, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी आदि शामिल है। इसके अलावा बिसाहूलाल सिंह, एन्दल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग का मंत्री बनना भी तय है। शेष बचे 20 स्थानों पर भाजपा अपने कई कद्दावर नेताओं के लिए जिसमें नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह, रामपाल सिंह, सीताशरण शर्मा, कुंवर विजय शह, जगदीश देवड़ा आदि नेताओं के लिए सुरक्षित रखे है।

यह वक्त भी गुजर जाएगा

✍ देवदत्त दुबे

इस समय सोशल मीडिया पर एक बात तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक बार अर्जुन ने कृष्ण से कहा इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो की खुशी में पढ़ो तो दुख हो और दुख में पढ़ो तो खुशी हो। तब कृष्ण ने लिखा यह वक्त भी गुजर जाएगा और हम सब लोगों को भी धैर्य बनाए रखना है क्योंकि यह वक्त भी गुजर जाएगा।

दरअसल सुख के दिन तेजी से व्यतीत होते हैं पता ही नहीं चलता और कष्ट के दिन थोड़े इंतजार करने वाले होते वर्तमान का इंतजार आपको लंबा नहीं लगेगा। जब आप इसकी तुलना मैं मिलने वाले जीवनदान से करेंगे क्योंकि जो घर पर वक्त गुजार रहा है वह अपना परिवार का समाज का और देश का जीवन बचाने में बड़ा योगदान दे रहा है क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए यदि आपने ऐसी कोई भूल की जिसमें आप बेवजह घर से निकले और यदि कहीं संक्रमित हो गए तो फिर यह छोटी सी भूल आपको और आपके परिवार को बहुत भारी पड़ने वाली है। इस विश्वव्यापी संकट को देखते हुए भी कुछ लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं वे अभी भी सामान्य दिनों की तरह वातावरण बनाए हुए इस महामारी का सबसे कमजोर पक्ष भी यही है कि करता कोई है और भरता कोई है। सोचो जिनके परिजन संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हैं उनके परिवार वाले उन्हें देखने भी नहीं आ सकते यहां तक कि मर जाने पर कई जगह परिवार वाले अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। जैसा कि इंदौर के डॉक्टर पंजवानी के तीनों बेटे ऑस्ट्रेलिया में थे और उन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए पिता का पार्थिव शरीर देखा ऐसी हजारों घटनाएं दुनिया में हो चुकी है।

जहां अस्पताल से सीधे श्मशान घाट लाशें भिजवाई गई सोचो इतने भयावह वातावरण में केवल घर के अंदर रहना ही जब सुरक्षित रख सकता है तो फिर बेसब्र क्यों होना। लॉक डाउन का समय बढ़ सकता है क्योंकि पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे यदि हमने लॉक डाउन का सत प्रतिशत पालन अब तक किया होता तो आगे समय बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती।अब भी समय है कि आज से ही प्रण करें की कुछ दिन की बात है, असुविधाओं मैं भी घर के अंदर ही रहेंगे पता नहीं क्यों इतने भयावह संकट के बाद भी देश के विभिन्न हिस्सों से जब ऐसी खबरें आती हैं, तो फिर सोचने पर विवश होना पड़ता है क्या लोग अभी सुधरने को तैयार नहीं है? जैसे कि मेरठ से खबर आई जहां झुग्गियों में कई खाने के पैकेट रखे हुए थे जबकि कुछ लोगों को नहीं मिले थे, यदि यह पैकेट एक घर में ना मिलकर सभी जगह बट जाते तो शायद लगता लोग महामारी से कुछ सबक ले रहे है ऐसी और भी खबरें आ रही हैं जहां आवश्यक वस्तुओं की कीमतें चौगुना तक बढ़ा दी है।

कुल मिलाकर यह जो प्राणों पर संकट आया है विश्वव्यापी है उससे निपटने के लिए हमें धैर्य रखना है, संयम रखना है और घर पर रहना है क्योंकि इतना तय है यह वक्त भी गुजर जाएगा। जिस चीन के वहान से इस महामारी की शुरुआत हुई वहां हालात अब सामान्य हो रहे यहां तो इतने हालात बिगड़े भी नहीं हैं इसलिए बहुत जल्दी स्थिति सामान्य होगी।

वैसे भी जीवन में समस्याओं का कोई अंत नहीं है कुछ लोगों के जीवन में तो पास की तरह समस्याएं आती जाती है। लेकिन 24 घंटे में 15 मिनट का योग हमें एक साक्षी भाव दे जाता है। बड़ी से बड़ी समस्याएं इस साक्षी भाव से आसानी से सुलझ जाएंगी जीवन में जब कोई भी विपरीत परिस्थिति, संघर्ष, चुनौती, परेशानी, दिक्कत और समस्या आती है तो हम उसका हिस्सा नहीं वही बन जाते हैं। समस्या और हम एक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम और क्रोध अलग-अलग हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तब हम ही गुस्सा बन जाते हैं। वही नुकसानदेह होता है साक्षी भाव को आप यूं भी समझ सकते हैं। आप किसी नाटक में काम कर रहे हैं तब अभिनय करने वाला कलाकार भी आप हैं और दर्शक भी स्वयं आप है। ऐसा करें कि गायक भी आप हो श्रोता भी खुद बने इस प्रयोग से हम खुद को खुद से ही देख सकेंगे जितना हम साक्षी भाव विकसित करेंगे उतना ही हम मन की शिफ्टिंग करने में दक्ष होंगे। अभी मन हमें लगाता हटाता है साक्षी भाव आने पर हम उसके गेयर बदल सकेंगे उसकी गति के क्लच गेयर और ब्रेक तीनों हमारे पास रहेंगे फिर कैसी भी घटना जीवन में हो शांति के साथ समाधान निकाल पाएंगे।

हर अंधेरी रात के बाद हर दिन जैसी सुबह आती है ऐसे यह दिन भी गुजर जाएंगे अच्छे दिन आएंगे धैर्य बनाए रखें घर पर ही रहे।

प्रयागराज शहर में

द सिटी स्टैन्डर्ड

अंग्रेजी समाचार पत्र

The City Standard

सम्पर्क . मो.- 7905230036, गोकरन शुक्ला - 8799689003

सिटी ऑफिस - 1 ए हाशिमपुर रोड, टेगोर टाऊन, प्रयागराज-211002

KASHYAP CLINIC Pvt. Ltd.

sexoLogist

ISO 9001 : 2015
ISO 13485 : 2003

हमारी शुभकामनाएं आपका आनंदमय जीवन

सुप्रसिद्ध साइको सेक्सोलॉजिस्ट

डा0 बी.के.कश्यप

आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा एवम् योग द्वारा उपचार

(आयुर्वेदाचार्य) नाड़ी विशेषज्ञ

BAMS, DNYS, APC. PARISHAD, NEW DELHI, Y.N.MAHARASHTRA, MUMBAI

राजेश मेडिकल हॉल

333,वेणी माधव मन्दिर,दारागंज,प्रयागराज Timing 9 am to 10 am

क्श्यप क्लीनिक, सिविल लाइन्स

30, नावाब युसुफ रोड,हाईकोर्ट पानी की टंकी,प्रयागराज Timing 11 pm to 8pm

8756999981, 8756999982, 8756999983, 8004999984

Web : www.drbkkashyapsexologist.com | E-mail : dr.b.k.kashyap@gmail.com
www.justdial.com Kashyap Clinic, Civil Lines, Allahabad - Fb : DrBkKashyap-09335410105/09889005053